

आनंद का सच्चा भाव

18 कैरेट रेट = ₹103903/-
(75.00%)

22 कैरेट रेट = ₹126900/-
(91.60%)

24 कैरेट रेट = ₹138523/-
(99.99%)

सोने का भाव* प्रति 10 ग्राम | GST Extra

anand
Jewels
Pandri, Raipur

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

आधी आबादी के 'हक' पर संसद में जंग

ये तीन विधेयक पेश

- संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026
- परिसीमन विधेयक, 2026
- संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026

haribhoomi.com

विलासपुर, शुक्रवार 17 अप्रैल 2026

मोदी की गारंटी- किसी राज्य के साथ नहीं होगा भेदभाव, प्रियंका बोलीं- बहकावे में न आएँ

केंद्र सरकार ने साल 2029 तक महिला आरक्षण को लागू करने और लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए तीन विधेयकों को गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। संसद में विपक्ष के विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिला को मिलने वाले अधिकार का जिस-जिस ने विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। शुक्रवार शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' और 'परिसीमन विधेयक, 2026' पेश किए, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026' पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े। इससे पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने विधेयकों को 'असंवैधानिक' करार देते हुए इन्हें पेश करने के समय पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल ने तीनों विधेयकों को भारत के संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा कि वास्तव में विधेयक इस समय लाने का क्या मकसद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी ▶▶ शेष पेज 8 पर

महिला आरक्षण समेत तीन बिल लोकसभा में पेश, आज शाम 4 बजे वोटिंग



प्रियंका बोलीं

महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे प्रधानमंत्री

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन को सत्ता बनाए रखने के लिए बहाने के तौर पर उपयोग करने और महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि यदि विधेयक पारित हो गया तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के वर्तमान संख्याखल 543 के आधार पर महिला आरक्षण को लागू करना चाहिए और जाति जनगणना के बिना परिसीमन नहीं होना चाहिए। प्रियंका ने गृह मंत्री अमित शाह पर राजनीतिक कुटिलता का आरोप भी लगाया और तंत कसते हुए कहा, यदि आज चाणक्य जिंदा होते तो आपकी कुटिलता से चौक जाते। उनका कहना था कि सच्चाई यह ▶▶ शेष पेज 8 पर

राहुल ने पूछा, 850 सीटों का गणित

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन और लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने की योजना पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने इस पूरी प्रक्रिया को सत्ता हथियाने की कोशिश और हिस्सा चोरी करार दिया। उनका आरोप है कि यह कदम महिला सशक्तिकरण के नाम पर असल में ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को छीनने की एक बड़ी कोशिश है। राहुल गांधी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और मेरीमैडरिंग के जरिए राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस और विपक्ष जातिगत जनगणना के बिना किसी भी ऐसे बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे जो पिछड़ों की भागीदारी को सीमित करता हो। राहुल ने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बरतते हुए सरकार की गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।

क्या है महिला आरक्षण बिल?

प्रस्तावित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक यानी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वां संविधान संशोधन) और परिसीमन विधेयक-2026' दोनों बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का अधिकार देता है। ये क्यों इतना जरूरी है? आजादी की 79 साल होने वाले हैं, लेकिन देश की आधी आबादी का संसद अमी प्रतिनिधित्व मात्र 14 प्रतिशत के आसपास ही है। महिलाओं के नीति निर्धारण में करने में पुरुषों का ही बहुमत रहता है। ऐसे में जरूरी है कि नीति निर्धारण में लैंगिक समता और महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

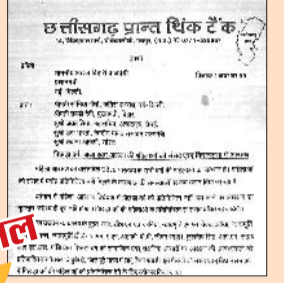
शाह ने समझाया कैसे आया 850 का आंकड़ा

अमित शाह ने कहा, सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती। यह भी झूठ है। जनगणना दो हिस्सों में होती है पहले मकानों को इंगित किया जाता है। फिर रहवासियों से पूछा जाता है। अमी मकानों की कोई जातीय व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं होती। 850 का आंकड़ा कहां से आया, मैं समझता हूँ। मारों 100 सीटें हैं जिसमें 33% आरक्षण देना है तो उसमें 50 सीटें बढ़ाते हैं तो सीटें 150 होती हैं। 850 राउंड ऑफ फिगर है। बिल जो सबन के सामने और कर्नाटक 28 सीटें हैं, यानि 5.15 प्रतिशत, बिल पारित होने के बाद, कर्नाटक में 28 से बढ़कर 42 सीटें हो जाएगी। ओंध प्रदेश 4.6 प्रतिशत, 4.65 प्रतिशत हो जाएगा। तेलंगाना- 17 सीटें हैं, जो कि 3.13 प्रतिशत है, बढ़कर 26 सीटें, 3.18 प्रतिशत। तमिलनाडु- 39 सांसद हैं, जो 7.18 प्रतिशत, जो कि अब 59 और 7.23 प्रतिशत होगा।

आज फिर वहीं मुद्दा देशभर में गरमाया है छत्तीसगढ़ में 28 साल पहले थिंक टैंक ने उठाई थी महिला आरक्षण की आवाज

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायपुर

इस समय देश की सियासत में महिला आरक्षण का मुद्दा जबरदस्त गरमाया है, लेकिन ये बात भी कम चौंकाने वाली नहीं है कि अब से 28 साल पहले यानि राज्य गठन के दो साल पहले राज्य के प्रबुद्ध जनों के थिंक टैंक ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण की मांग रखी थी। इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, समेत सोनिया गांधी, उमा भारती और रावड़ी देवी के समक्ष भी यही मुद्दा उठाया था। इस थिंक टैंक से जुड़े सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अवधराम चंद्रकार का कहना है कि 28 साल पहले उठाई गई मांग आज भी प्रासंगिक है। एसटी,एससी के साथ ओबीसी महिलाओं को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना ही चाहिए।



तब की आशंकाएं आज भी प्रासंगिक

हाल में यह भी उल्लेख था कि यदि आरक्षण में संतुलन नहीं रखा गया, तो सत्ता का केंद्रीकरण एक विशेष वर्ग में हो सकता है और इससे अस्थावर व अस्थायता बढ़ने की आशंका रहेगी। आज, जब महिला आरक्षण को लेकर कई बहस चल रही है, वही सवाल फिर उठ रहे हैं—क्या आरक्षण में सभी वर्गों को महिलाओं को समान अवसर मिलना/बना करना, पुरानी बहस/हल के वर्षों में महिला आरक्षण को लेकर संसद में कानून पारित होने के बाद यह मुद्दा फिर चर्चा में है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है, जिसके कारण इसे लागू होने में समय लग सकता है। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में अब यह मांग उठ रही है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया जाए, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे।

1998 में संगठित पहल

छत्तीसगढ़ प्रान्त थिंक टैंक द्वारा 1 नवम्बर 1998 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने की मांग की गई थी। ज्ञापन में विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया गया था। उस समय यह चिंता जताई गई थी कि यदि महिला आरक्षण में सामाजिक वर्गों का संतुलन नहीं रखा गया, तो इसका वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और केवल सीमित वर्ग को महिलाओं की ही लाभ मिलेगा।

सामाजिक संतुलन की थी मुख्य चिंता

ज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित होना ▶▶ शेष पेज 8 पर

मंत्री पहुंचे प्लांट कांग्रेस की टीम भी पहुंची

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जांगगीर चाम्पा

सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट के बायलर हादसे के मामले में पुलिस ने वेदांता प्रबंधन से जुड़े 19 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 16 लोग घायल हैं, जिनमें से आधे से अधिक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। गौरतलब है कि मंगलवार 14 अप्रैल को डभरा ब्लॉक के सिंघीतराई स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में बायलर फटने की घटना हुई थी। इस भीषण हादसे में तीन दर्जन से अधिक श्रमिक वृत्ती तर से ▶▶ शेष पेज 8 पर

बायलर विस्फोट में वेदांता के 19 पर केस, जांच में खुल रही लापरवाही



प्रारंभिक जांच में उजागर हुई लापरवाही

घटनास्थल पर मौजूद बायलर मुख्य निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक तक्रामीकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि बायलर फटने के भीतर अत्यधिक मात्रा में ईंधन के जमा हो जाने के कारण तेज दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे बायलर में विस्फोट हुआ। उत्पन्न दबाव के कारण बायलर का निचला भाग अपनी निर्धारित स्थिति से हट गया, जिसके परिणामस्वरूप यह गंभीर दुर्घटना हुई। इसी प्रकार एफएसएल सक्ती द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में भी यह पुष्टि की गई है कि अत्यधिक ईंधन संतय और उससे उत्पन्न अतिरिक्त दबाव ही विस्फोट की मुख्य वजह रहे। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वेदांता कम्पनी तथा एन.जी.एस.एल. द्वारा मशीनरी एवं ▶▶ शेष पेज 8 पर

उद्योग मंत्री पहुंचे वेदांता

कलेक्टर-एसपी और कंपनी प्रबंधन के साथ की समीक्षा बैठक

बायलर ब्लास्ट के बाद उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने 16 अप्रैल को सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक के चाम्पा सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन और प्लांट प्रबंधन के अधिकारियों के साथ उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृत श्रमिकों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मंत्री देवांगन ने सिंघीतराई में ही कलेक्टर अमृत विकास तोपा, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर और वेदांता प्रबंधन के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने श्रम कर्मियों के अनुसूचित घटना के तक्रामीकी पहलुओं को गहराई से जांच करने तथा दोषियों के विरुद्ध एक-आड़-आर दवां करने के निर्देश दिए।

पत्नी का मरण-पोषण करना पति का कर्तव्य

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पति का अपनी पत्नी का भरण-पोषण करने का दायित्व एक प्राथमिक और निरंतर कर्तव्य है। इसे इस तरह से निभाया जाना चाहिए जिससे पत्नी गरिमापूर्ण जीवन जी सके। कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक महिला के गुजारा भत्ता की राशि को 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करते हुए कीं। मामले के अनुसार, महिला का विवाह सात मई, 2023 को नयी दिल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। महिला के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्द्रपूर्ण नहीं रहे और ससुराल में रहने के दौरान उसे उपेक्षा और शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में, पत्नी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 144 के तहत टनकपुर, जिला चंपावत स्थित सक्षम न्यायालय में कार्यवाही शुरू की और 50,000 रुपये प्रति माह के गुजारा भत्ता की मांग की। चंपावत स्थित पारिवारिक अदालत ने पत्नी को 8,000 रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इस राशि से असंतुष्ट होकर पत्नी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने इस राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।

SIKSHA 'O' ANUSANDHAN

SAAT-2026

Empowering students for a brighter future

B.TECH PROGRAMMES IN EMERGING COMPUTING

- Computer Science and Engineering (AI and ML)
- Computer Science and Engineering (Cyber Security)
- Computer Science and Engineering (Data Science)
- Computer Science and Engineering (Internet of Things)

APPROVAL & RECOGNITIONS

- Approved by UGC and AICTE
- Re-accredited by NAAC with A++ Grade
- Granted with Category-1 Graded Autonomy by UGC
- NBA Accredited Programmes

MIRF INDIA RANKINGS 2025

- 15th Best in University Category
- 22nd Best in Engineering Category

INTERNATIONAL RANKINGS 2026

- Ranked in QS World Rankings 2026
- Ranked in Times World Rankings 2026

To apply for admission through SAAT, Please visit: www.soa.ac.in

10th Anniversary

सोने का सच्चा भाव

कल भी, आज भी और कल भी

मार्केट रेट* = ₹142600/-
22 kt. कैरेट
Corporate Rate as per their website
Date 16/04/2026 - Time 08:21 PM

आनंद का सच्चा भाव = ₹126900/-
22 kt. कैरेट

आपका फायदा ही फायदा = ₹15700/-
22 kt. कैरेट

22 kt. कैरेट (91.60%) BIS HUID Hallmark Jewellery

anand
Jewels
Pandri, Raipur

* नई सात, नौ, बीस और अठारह कैरेट का भाव। पुराने भाव, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 कैरेट का भाव। - सभी का TradeMark & Copyright. आनंद ज्वेलर्स (इंटरनेट) प्रा. लि. के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं।

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी



7 भाग
घायल जवानों की कहानी उन्हीं की जुबानी

सुकमा जिले में डीआरजी में पदस्थ जांबाज राजेन्द्र कुमार नाग ने महज पांच साल में अपनी टीम के साथ कई मुठभेड़ में शामिल रहकर 61 नक्सलियों को मार गिराया। लेकिन करंगुड़ा हिल्स में सबसे लंबे समय लगभग 22 दिन तक नक्सलियों के खिलाफ चले ऑपरेशन के दौरान वे आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए और उन्हें अपना दाहिना पैर घुटने के नीचे से खोना पड़ा। घायल जवानों की कहानी उन्हीं की जुबानी के सातवें भाग में हम राजेन्द्र कुमार नाग की वीरता, त्याग और अदृष्ट संकल्प की कहानी बताने जा रहे हैं, जो देश सेवा के लिए पुलिस में भर्ती हुए। अब जिंदगी भर देश सेवा करने का उनका सपना अधूरा रह गया, जिसका उन्हें दुख है लेकिन नक्सलवाद के खात्मे से वे काफी खुश हैं।

61 नक्सलियों को मारने के बाद जवान ने गंवाया पैर और जीवन भर सेवा की हसरत अधूरी रह गई, पर अब खुश

राजेश दास ►► जगदलपुर

राजेन्द्र कुमार नाग अपनी टीम के साथ 27 अप्रैल को तंरम, सिलगेर, आवापल्ली होते हुए पुजारी कांकर होते हुए सुबह करंगुड़ा हिल्स के नीचे पहुंचे। हिल्स के ऊपर चढ़ने के दौरान जगह-जगह नक्सलियों ने आईईडी प्लांट कर रखा था। दर्जनों आईईडी बरामद कर ►►शेष पेज 8 पर



पहली बार करंगुड़ा हिल्स में उतरा वायुसेना का हेलीकाप्टर

दोनों घायल जवानों को लेने के लिए पहली बार करंगुड़ा हिल्स के ऊपर वायुसेना के हेलीकाप्टर को उतारा गया और दोनों घायल जवानों को गलगाम स्थित सीआरपीएफ कैम्प ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को एक अन्य चौपर से रायपुर ले जाया गया। रायपुर के श्री नारायण अस्पताल में राजेन्द्र कुमार को तथा संतोष को रामकृष्ण अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। राजेन्द्र 5 जून को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और वापस सुकमा लौटे। वर्तमान में वे पुलिस लाइन सुकमा में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं।

हौसला कमी नहीं खोया लेकिन नक्सलवाद खत्म होने की खुशी

विनेद ने बताया कि घायल होने के बाद पुलिस विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है। अभी भी वे हर माह उपचार के लिए विभाग के सहयोग से रायपुर जाते हैं। पर गंवाये व दाएं कान में कम सुनाई देने के बाद भी उनका हौसला बरकरार है। हालांकि घायल होने के बाद देश के लिए अंतिम दम तक कुछ करने की तमन्ना अधूरी रह गई। लेकिन अब भी विभाग में रहते हुए वे बस्तर की शांति व देश के लिए कुछ करते रहना चाहते हैं।



जवानों ने अदम्य साहस कर्तव्यनिष्ठा व सर्वोच्च बलिदान

बस्तर रेंज में शांति सुरक्षा और विकास की स्थापना का संघर्ष दशकों से जारी रहा है। माओवादी हिंसा से प्रभावित इस क्षेत्र में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सुरक्षाबलों ने हिपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इन प्रयासों के दौरान अनेक जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
- सुंदरराज पट्टिलिंगम आईजी बस्तर



खबर संक्षेप

दुर्ग आने वाली ट्रेन में 'ब्रेक बाइंडिंग'

चाईबासा। झारखंड में गुरुवार को दक्षिण पूर्वी रेलवे के चक्रधरपुर संभाग में आरा-दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस के कई डिब्बों से धुआं निकलने लगा। यह घटना 'ब्रेक बाइंडिंग' की समस्या के कारण हुई। ट्रेन में 'ब्रेक बाइंडिंग' की समस्या आई जिसके कारण चक्रधरपुर संभाग में दो स्थानों पर ट्रेन के डिब्बों से धुआं निकलने लगा। रेलवे कर्मचारियों ने इसे देखा और ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। ब्रेक संबंधी दिककत ठीक की गयी। यह घटना दो स्थानों पर हुई।

स्कूलों की बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़। चंडीगढ़ और पंजाब के बरनाला में गुरुवार को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ई-मेल मिले। गहन जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। बम की धमकियों की जानकारी मिलने के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ते, श्वान दस्ते और एम्बुलेंस व इमकल विभाग सहित अन्य दलों को तुरंत स्कूलों में भेजा गया। बरनाला के छह स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले थे। धमकियों की सूचना मिलते ही विस्फोटक एवं सुरक्षा जांच दलों और संबंधित थाना पुलिस सहित सभी अधिकारियों को सक्रिय कर दिया गया।

बस पलटी, तीन यात्रियों की मौत, 20 घायल

कोटा। कोटा में स्लीपर बस के एक्सीडेंट में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा पैसंजर्स घायल हैं। यात्रियों का दावा कि बस के फ्रंट गियर पर किसी ने पत्थर मारा था, इसलिए ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। अनियंत्रित होने के कारण बस डिवाइडर पाक कर दूसरी लेन में घुसकर पलट गई। पलटने के कारण टूटें कांच वाले हिस्से से पैसंजर्स बाहर सड़क पर गिर गए।

जांच में आय से ज्यादा खर्च होने का दावा, 38.8 लाख की संपत्ति 10 साल में हुई 3.32 करोड़

शराब घोटाले में अब आय से अधिक संपत्ति का केस, पूर्व विशेष सचिव और पत्नी पर एफआईआर

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

सीबीआई जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार वर्ष 2013 में एपी त्रिपाठी की कुल संपत्ति 38.08 लाख रुपए थी, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 3.32 करोड़ रुपए हो गई। सीबीआई जांच में सामने आया है कि एपी त्रिपाठी ने इन 10 वर्षों में अपनी पत्नी मंजुला त्रिपाठी के साथ मिलकर वैध आय से करीब 4.91 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 54.53 प्रतिशत ज्यादा है।

सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि जांच अवधि (1 फरवरी 2013 से 22 दिसंबर 2023) के दौरान पंजीत की कुल आय करीब नौ करोड़ रुपए रही, जबकि उनका खर्च 10.97 करोड़ रुपए से अधिक पाया गया। इस खर्च में विदेशी लेन-देन, म्यूचुअल फंड निवेश, कारपोरेट निवेश और अन्य निजी व्यय शामिल हैं, जो घोषित आय से मेल नहीं खाते। पड़ताल में त्रिपाठी इन विसंगतियों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।

राज्य के चर्चित तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाले में सीबीआई ने पहली बार आबकारी विभाग के तत्कालीन विशेष सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएस) के पूर्व प्रबंध संचालक अरुणपति त्रिपाठी तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का अपराध दर्ज किया है। सीबीआई ने एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

दो साल बाद अपराध दर्ज

शराब घोटाले की जांच ईडी के बाद सीबीआई को 21 दिसंबर 2024 को ट्रांसफर की गयी। केस ट्रांसफर होने के दो साल बाद सीबीआई ने एपी त्रिपाठी तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का अपराध दर्ज किया है। शराब घोटाला प्रकरण में सीबीआई के अफसर आबकारी विभाग के अफसरों से पूछताछ कर सकते हैं।



कई शहरों में चल-अचल संपत्ति

जांच एजेंसियों के दलों के मुताबिक एपी त्रिपाठी का रायपुर के लामाडी क्षेत्र में प्लैट, नया रायपुर के प्रीमियम गोलफ कोर्स इलाके में संपत्ति, दुर्ग जिले में जमीन, गिलाई में मकान, आम्बुषण और बैंक बैलेंस समेत कई चल अचल संपत्तियां हैं।

सिंडिकेट के मास्टरमाइंड

इंडियन टेलिकॉम सर्विस से प्रतिभियुक्ति पर छत्तीसगढ़ आए अरुणपति त्रिपाठी पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 से 2023 के बीच सरकारी शराब दुकानों के माध्यम से अवैध शराब बिक्री को बढ़ावा दिया और पूरे सिंडिकेट के संचालन में अहम भूमिका निभाई। शराब खरीदी करने से लेकर शराब आपूर्ति करने तथा बिक्री करने में एपी त्रिपाठी की प्रमुख भूमिका रही है।

तीन दर्जन से अधिक अधिकारी जांच के दायरे में

इस कार्रवाई के बाद तीन दर्जन से अधिक अधिकारी जांच के दायरे में हैं। इससे पहले ईओडब्ल्यू-एसीबी की जांच में पूर्व मुख्य सचिव विवेक दांड, पूर्व आईएसएस अबिल टूटजा, निरंजन दास समेत करीब 70 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका है। इनमें से कई अधिकारियों पर छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो चुकी है।

34 साल बाद आमने-सामने बातचीत

इजराइल और लेबनान 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत : ट्रंप

काहिरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि इजराइल और लेबनान 10 दिनों के संघर्षविराम पर सहमत हो गए हैं। यह घोषणा वाशिंगटन में दशकों बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी राजनयिक वार्ता के दो दिन बाद हुई है। ट्रंप ने कहा कि यह संघर्षविराम पूर्वी समयानुसार आज शाम पांच बजे से शुरू होगा। यह संघर्षविराम लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिज्बुल्ला के बीच एक महीने से अधिक समय से जारी लड़ाई के बाद हुआ है। लेबनान ने इजराइल और हिज्बुल्ला के बीच लड़ाई रोकने के लिए आगे की बातचीत से पहले संघर्षविराम ►►शेष पेज 8 पर

मोदी और मैक्रों ने पश्चिम एशिया पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। मोदी ने मैक्रों के साथ हुई बातचीत के बारे में 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करने जा रही हैं। इससे पहले, मोदी और मैक्रों ने पांच मार्च को फोन पर बात ►►शेष पेज 8 पर

16 राज्यसभा सदस्यों में से आठ भाजपा के सांसद

नितिन नवीन समेत नवनिर्वाचित सदस्यों ने रास की सदस्यता की ली शपथ

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, छत्तीसगढ़ से भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलो देवी नेताम सहित 16 न व नि व र्चि त / पुनर्निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों ने गुरुवार को पद की शपथ ली। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले इन सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इन 16 सांसदों में से आठ भाजपा के हैं, जबकि उसके सहयोगी ►►शेष पेज 8 पर

भाजपा अध्यक्ष ने हिंदी में ली शपथ

भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देकर उच्च सदन का रुख किया है। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। सदन में मौजूद सदस्यों ने मेजे थपथपाकर उनका स्वागत किया। नवीन उच्च सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने उन्हें और शपथ लेने वाले अन्य सदस्यों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भी शपथ ली, जो बिहार से पुनर्निर्वाचित हुए हैं।

दो होनहारों ने 99 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल कर टॉप का पाया तमगा

छत्तीसगढ़ में टॉप पर डीपीएस दुर्ग जुनवानी सभी बच्चे पास, इनमें 90 प्लस वाले 45

हरिभूमि न्यूज़ ►► गिलाई

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में डीपीएस दुर्ग जुनवानी का राज्य में दबदबा रहा है। यहां सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। खास बात यह है कि 45 बच्चों ने 90 प्लस हासिल किए हैं। दो होनहारों ने 99 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल कर टॉप का तमगा पाया है। जुनवानी स्थित डीपीएस दुर्ग के दो होनहार छात्र अश्वरथ और दिव्या वशिष्ठ ने 99 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर स्कूल का नाम राज्य में रोशन किया है। अश्वरथ ने 99.4 प्रतिशत और दिव्या वशिष्ठ ने 99.2 प्रतिशत ►►शेष पेज 8 पर

डॉक्टर बनना चाहती हैं दिव्या
स्कूल की दूसरी टॉपर दिव्या वशिष्ठ ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, स्कूल के टीचर, अपने माता पिता, अनुशासन और समय प्रबंधन को दिया। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि आगे चलकर वो बड़ी डॉक्टर बनें।



बड़ा वकील या बिजनेसमैन बनने का सपना

विद्यालय के टॉपर अश्वरथ ने हरिभूमि को बताया कि वो अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन को देना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा अपना लक्ष्य को स्पष्ट रखा और नियमित पढ़ाई पर फोकस किया। अश्वरथ 11वीं में कॉमर्स विषय लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं और भविष्य में बड़ा वकील या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। अश्वरथ के माता-पिता ने भी बेटे की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि यह पूरे परिवार के लिए मोरच का क्षण है। उन्होंने बताया कि अश्वरथ ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी और अधिकतर समय सेल्फ स्टडी के जरिए तैयारी की।

SAWANSUKHA
Gold | Diamond | Jadau

हाँ ये सच है!

मेकिंग चार्जेस **ज़ीरो** से शुरू

पुराना सोना एक्सचेंज करने पर पूरा मूल्य

मनायें अक्षय तृतीया • 12-20th अप्रैल

91470 75332 Raipur: Sadar Bazar | Kolkata | Siliguri

चिंतन

महिला हित में राजनीति से ऊपर उठें सभी दल

भारतीय लोकतंत्र में लंबे इंतजार के बाद महिला आरक्षण को लेकर आया "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" केवल एक विधायी पहल नहीं, बल्कि सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। दशकों से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का तात्का खोलता है। ऐसे समय में जब संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित रही है, यह पहल लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधिक और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में सभी विपक्षी दलों को चाहिए कि वे महिला हित में राजनीति से ऊपर उठें और इस बिल का समर्थन करें। हालांकि तेलंगाना, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कुछ राज्य इसके विरोध में हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक पहल के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है। वह विपक्षी दलों में श्रेय लेने की होड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से यह कहकर कि "आप बने लीजिए, लेकिन महिला हित में समर्थन दें।", एक तरह से उस राजनीतिक मानसिकता को उजागर किया है, जहां मुद्दे से ज्यादा महत्व श्रेय को दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या देश की आधी आबादी के अधिकार भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की भेंट चढ़ेंगे? यह विधेयक केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है। आज संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14-15 प्रतिशत के आसपास है, जो लोकतांत्रिक संतुलन के लिहाज से अपर्याप्त है। ऐसे में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नीति-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगा और निर्णयों को अधिक संवेदनशील तथा समावेशी बनाएगा। यह 'महिला विकास' से आगे बढ़कर 'महिला-नेतृत्व विकास' की दिशा में एक वैचारिक बदलाव भी है। फिर भी, इस पहल के साथ कुछ गंभीर सवाल जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता इसका कार्यान्वयन है, जिसे परिसीमन और जनगणना से जोड़ दिया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि यह कानून 2029 तक ही प्रभावी हो पाएगा। क्या यह देरी अनिवार्य है या राजनीतिक साधन तैयार करने में बाधा बन सकती है। लोकतंत्र में निरंतरता और अनुभव का महत्व कम नहीं आंका जा सकता, इसलिए इस व्यवस्था पर गंभीरता से पुनर्विचार आवश्यक है। विपक्ष द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण का अभाव। यदि महिला आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचता, तो यह सशक्तिकरण अधूरा रह जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि इस कानून के क्रियान्वयन में सामाजिक न्याय के व्यापक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए। आज जरूरत इस बात की है कि सभी दल इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठें। यह केवल सत्ता या विपक्ष का सवाल नहीं, बल्कि समाज के संतुलित विकास का प्रश्न है। महिला सशक्तिकरण को यदि सच में राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना है, तो इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से अलग रखना होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक अवसर है भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संतुलित और संवेदनशील बनाने का, लेकिन यह अवसर तभी सार्थक होगा, जब इसे ईमानदारी से लागू किया जाए और राजनीतिक दल इसके पीछे छिपे व्यापक उद्देश्य को समझें।



संसद सत्र

डॉ. सतीश पूनिया

यह भारतीय जनता पार्टी की देश की आधी आबादी को उनका वांछित अधिकार दिलाने की मंशा और इच्छाशक्ति का भी सत्र है। गुरुवार को संसद में उनका वांछित अधिकार दिलाने की मंशा और इच्छाशक्ति का भी सत्र है। गुरुवार को संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक 2026 और केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 सदन में प्रस्तुत किए गए। इसके माध्यम से विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश और दुनिया ने यह अनुभव किया है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सशक्त किया गया है। इसके लिए महिला आध्यात्मिक अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने की उसी मंशा के अनुरूप मोदी सरकार विधानसभा और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण के प्रावधान को शीघ्र लागू करने की दिशा में पहल की है। भारत पुरातन प्रवाह का राष्ट्र है। एक विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और विरासत के कारण विश्व में एक पहचान वाला राष्ट्र है। जहां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नताएं होते हुए भी 'अनेकता में एकता' ऐसा दृश्य परिलक्षित होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्णता के लिए भी माना जाता है। आज विश्व के मानचित्र पर भारत की एक आत्मनिर्भर स्वाभिमानी राष्ट्र की पहचान है। भारत के लोकतंत्र को दृढ़ता भारत के संविधान ने दी है जो एक वैशिष्ट्य लिए हुए है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में बखूबी उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों ने इसे और पुष्ट किया है, इसलिए लैंगिक समानता के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह उल्लेख अहम रहा है कि गांधी, मैत्रेयी के पुरातन परंपरा के देश में महिलाओं यानि आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि शासन में, निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही नारी के उत्थान और उत्कर्ष में पूर्वक अपना योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को उनका वांछित अधिकार दिलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसके नेतृत्व की महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति का ही आईना है। भारतीय जनसंघ और भाजपा के वैचारिक स्तंभ पंडित

महिला आरक्षण: नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति

सद का यह विशेष सत्र भारतीय संसद के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की देश की आधी आबादी को उनका वांछित अधिकार दिलाने की मंशा और इच्छाशक्ति का भी सत्र है। गुरुवार को संसद में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026 सदन में प्रस्तुत किए गए। इसके माध्यम से विधायिका में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश और दुनिया ने यह अनुभव किया है कि भारत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सशक्त किया गया है। इसके लिए महिला आध्यात्मिक अनेक योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। महिलाओं को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने की उसी मंशा के अनुरूप मोदी सरकार विधानसभा और संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से महिला आरक्षण के प्रावधान को शीघ्र लागू करने की दिशा में पहल की है। भारत पुरातन प्रवाह का राष्ट्र है। एक विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और विरासत के कारण विश्व में एक पहचान वाला राष्ट्र है। जहां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नताएं होते हुए भी 'अनेकता में एकता' ऐसा दृश्य परिलक्षित होता है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आधुनिक युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्णता के लिए भी माना जाता है। आज विश्व के मानचित्र पर भारत की एक आत्मनिर्भर स्वाभिमानी राष्ट्र की पहचान है। भारत के लोकतंत्र को दृढ़ता भारत के संविधान ने दी है जो एक वैशिष्ट्य लिए हुए है, जिसमें नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में बखूबी उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकारों ने इसे और पुष्ट किया है, इसलिए लैंगिक समानता के अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह उल्लेख अहम रहा है कि गांधी, मैत्रेयी के पुरातन परंपरा के देश में महिलाओं यानि आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि शासन में, निर्णयों में भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही नारी के उत्थान और उत्कर्ष में पूर्वक अपना योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को उनका वांछित अधिकार दिलाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उसके नेतृत्व की महिलाओं के प्रति संवेदनशील नीति का ही आईना है। भारतीय जनसंघ और भाजपा के वैचारिक स्तंभ पंडित

दीनदयाल उपाध्याय अपने 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांत में समाज को एक जीवंत इकाई के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार, समाज के प्रत्येक अंग का सशक्त होना आवश्यक है और नारी इसमें केंद्रीय भूमिका निभाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरुष और स्त्री परस्पर पूरक हैं। किसी एक की उपेक्षा राष्ट्र को कमजोर बना देती है। यह दर्शन आज मोदी सरकार की नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहां महिला सशक्तिकरण को केवल सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पुनरुत्थान का आधार माना गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की



भागीदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का साहसिक प्रयास किया, भले ही वह उस समय राजनीतिक बाधाओं के कारण सफल नहीं हो सका। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनधन योजना शुरू हुई तो देश की 32 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। आज देश की बेटियां नए-ए बिजनेस में अपनी पहचान बना रही हैं। मुद्रा योजना में 60% से ज्यादा लोन महिलाओं ने लिए हैं। देश की स्टार्टअप क्रांति को भी महिलाएं लीड कर रही हैं। आज 42% से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। यह हमारे लिए, देश के लिए और देश की आधी आबादी के लिए गौरव की बात है कि इस समय हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर वित्त मंत्री जैसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही हैं। उन्होंने देश की गरिमा और गौरव, दोनों को बढ़ाया है। साल 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। तब एक सुर में ये बात भी उठी थी कि इसे हर हाल में 2029 तक लागू हो जाना चाहिए। खासकर, हमारे विपक्ष के सभी साथियों ने मुखर होकर इस बात पर जोर डाला था कि 2029 में

ये लागू हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उसी संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो ठोस कदम उठाए गए हैं, उन्होंने समाज की संरचना को बदलने का कार्य किया है। फिर चाहे वह सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण की बात हो, या फिर 'प्रधानमंत्री उज्वला योजना' के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास हो। यह योजनाएं केवल सुविधाएं नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मसम्मानी बनाने के साधन हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के मोर्चे पर भी मोदी सरकार लगातार महिलाओं के लिए कार्य कर रही है। जन-धन खातों, स्वयं सहायता समूहों और मुद्रा योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। आज ग्रामीण भारत में लाखों महिलाएं उद्यमिता की ओर अग्रसर हैं। लखपति दीदी के माध्यम से मोदी सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने का काम किया है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे अभियान के माध्यम से महिलाओं के प्रति समाज की सोच में क्रांतिकारी बदलाव लाने में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किया। इस अभियान से निश्चित रूप से सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन आया है। इसका परिणाम भी हमें पिछले दस-ग्यारह वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिला है। खेल, विज्ञान, शिक्षा, राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में देश की महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण तो मिला, लेकिन लंबे समय तक 'सरपंच पति' जैसी प्रवृत्तियां इस व्यवस्था को कमजोर करती रहीं।

मोदी सरकार ने 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' के माध्यम से इस प्रवृत्ति को चुनौती दी है। सशक्त पंचायत - नेत्री अभियान जैसी महत्वपूर्ण पहल से पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त किया गया। 4 मार्च 2025 को नई दिल्ली में 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' का शुभारंभ किया गया। वर्षों की जड़ता और संघर्ष तथा विमर्श के बाद मोदी सरकार में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक उल्लेखनीय, ऐतिहासिक एवं स्तुत्य कदम है। 2029 तक संसद और विधानसभाओं में 33% महिला प्रतिनिधित्व को लागू करने का केवल एक आर्थिक शक्ति, बल्कि एक न्यायपूर्ण और समावेशी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा।

(लेखक काज्या हरिगण प्रसादी हैं। वे उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आधी दुनिया

महेन्द्र तिवारी



लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का भविष्य

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के स्तर पर यह लंबे समय तक आधा अधूरा रहा है क्योंकि जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा होने के बावजूद महिलाएं राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हो पाई हैं। इसी ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से 2023 में पारित संविधान का संशोधन अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सामने आया। यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी उप आरक्षण शामिल है। यह कानून लगभग 27 वर्षों से चल रही बहस और राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। 19 सितंबर 2023 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 तथा 21 सितंबर को दोनों सदनो से पारित कर दिया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह संविधान का हिस्सा बन गया। इस अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझने के लिए वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। आज लोकसभा की 543 सीटों में से केवल 74 सीटों पर महिलाएं हैं, जो लगभग 13.6 प्रतिशत हैं। यह संख्या 2019 के 78 से थोड़ी कम है। वहीं देशभर में कुल 4666 सांसदों और विधायकों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत के आसपास है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 8360 उम्मीदवारों में केवल 797 महिलाएं थीं, यानी लगभग 9.6 प्रतिशत, और लगभग 28 प्रतिशत सीटों पर कोई महिला प्रत्याशी ही नहीं था। यह आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अभी भी संरचनात्मक बाधाओं से घिरी हुई है। इसके विपरीत यदि पंचायती राज संस्थाओं को देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां महिलाओं की भागीदारी लगभग 46.6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और कई राज्यों में यह 50 प्रतिशत से भी अधिक है। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जब आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाता है तो महिलाएं न केवल प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं बल्कि प्रभावी नेतृत्व भी प्रस्तुत करती हैं। वैश्विक तुलना में भी भारत पीछे है। रवांडा में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 64 प्रतिशत है, न्यूबा में 53 प्रतिशत, निकारगुआ में 52 प्रतिशत और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत। इस परिप्रेक्ष्य में भारत का आंकड़ा अपेक्षाकृत कम है, जो यह दर्शाता है कि केवल लोकतांत्रिक ढांचा पर्याप्त नहीं है, बल्कि समावेशी नीतियों की भी आवश्यकता होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से जुड़ी शर्तें इसे जटिल बना देती हैं। अधिनियम में जोड़ा गया अनुच्छेद 334ए यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं होगा, जब तक अगली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसका अर्थ यह है कि कानून पारित होने के बावजूद इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखेगा। यही बिंदु इस अधिनियम की सबसे बड़ी अलोचना का कारण भी बना हुआ है। 2021 की जनगणना पहले ही टल चुकी है और अब यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि नई जनगणना 2026 के बाद होगी। इसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया भी समय लेगी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि महिलाओं का आरक्षण 2029 या उससे भी बाद के चुनावों में लागू हो सकता है। इस देरी को कई विशेषज्ञ न्याय में विलंब के रूप में देखते हैं। हालांकि सरकार और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के सीटों का पुनर्वितरण करना उचित नहीं होगा। संविधान के अनुसार परिसीमन एक आवश्यक प्रक्रिया है ताकि प्रतिनिधित्व समान और संतुलित रहे। इस प्रकार यह बहस केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संवैधानिक भी है। इस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सिद्धांत रूप में अत्यंत प्रगतिशील है, लेकिन व्यवहार में कई जटिलताओं से घिरा हुआ है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी शीघ्रता और प्रभावशीलता के साथ लागू किया जाता है। यदि जनगणना और परिसीमन की प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कर लिया जाता है तो यह अधिनियम भारत के लोकतंत्र को अधिक समावेशी और संतुलित बना सकता है। अन्यथा यह केवल एक अधूरी संभावना बनकर रह सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं। वे उनके अपने विचार हैं।)

संघर्ष से आती है जीवंतता



संकलित

दर्शन

साधना संसार में है, जंगल में तो साधना का सवाल ही नहीं है। साधना यहां है, जहां प्रतिपल कांटे हैं। कांटों के बीच जिस दिन तुम चलना सीख लो और कांटों के बीच तो चलो और कांटे चुभें न, बस उसी दिन समझ लोना कि अब तुम योग्य हो गए। जानल जाने की जरूरत भी क्या है। यहीं भीड़ में जंगल हो गया है, अगर तुम्हारे भीतर प्रौढ़ता आ जाए, तो प्रज्ञा का जन्म हो। प्रज्ञा का जन्म संघर्षण से होता है। प्रतिपल जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने से होता है। हारने, गिरने, उठने से होता है। हजार बार गाली दी जाएगी, तुम क्रोधित हो जाओगे। हजार बार के अनुभव से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अपने को जलाना व्यर्थ है। गाली कोई दूसरा दे रहा है, दंड अपने को देना व्यर्थ है। एक दिन तो ऐसा आएगा कि कोई दूसरा गाली देगा और तुम्हारे भीतर क्रोध न आएगा। उसी दिन तुम्हारे भीतर एक कांटा फूल बन गया। उस दिन तुम्हें जो शांति मिलेगी, कोई जंगल नहीं दे सकता। जंगल की शांति मुर्दा है। अगर यहां गालियों के बीच तुम शांत हो गए, तो तुम्हारी शांति में एक जीवंतता होगी। जंगल की शांति में सननाटी है, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। वह नकारात्मक है। संसार में अगर तुम शांत हो जाओ तो सकारात्मक है। जंगल की शांति मरने जैसी है, संसार की शांति बड़ी जीवंत है। परमात्मा को पाना है, तो भागना मत। भगोड़ों से परमात्मा का कभी कोई संबंध नहीं जुड़ता। कार्यों से संबंध जुड़ भी कैसे सकता है? चुनौती स्वीकार करने वाला साहस चाहिए।

अंतर्मन



करंट अफेयर

लंदन में भारतीय उच्चायोग ने आंबेडकर की जयंती मनाई

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने पुष्पांजलि अर्पित कर 'भारत रत्न' डॉ. बी. आर. आंबेडकर की 136वीं जयंती मनाई और समानता के बाबासाहेब के संदेश पर विचार साझा किया। बुधवार शाम को 'इंडिया हाउस' के आंबेडकर हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 'फेडरेशन ऑफ अंबेडकरग्रुप एंड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन' (एफएबीओ) ब्रिटेन के सदस्यों, छात्रों और समुदाय के नेताओं द्वारा भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के दूरगामी सामाजिक-आर्थिक योगदान की प्रशंसा में कायात्मक प्रस्तुतियों से मालाही जीवंत हो उठा। इस मौके पर आंबेडकर के जीवन और करियर की कई प्रमुख घटनाओं को शामिल करते हुए एक वीडियो दिखाया गया, जिसमें लंदन में विधि छात्र के रूप में बिताये गए उनके समय को भी प्रदर्शित किया गया। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुर्ईय्यामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'आंबेडकर का यह संदेश कि लोकतंत्र का सार इस विचार में निहित है कि हम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करें, एक आधुनिक राष्ट्र के लिए काफी महत्व रखता है।' उन्होंने कहा, और बेशक, यह एक ऐसी यात्रा है जो न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में अब भी जारी है। हम लगातार अस्मानता और लैंगिक एवं सामाजिक आधार पर हिंसा के दौर में जी रहे हैं।



कोयला और चंदन



संकलित

प्रेरणा

चौधरी पहलवान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा-देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर लो लाओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुस्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले- बेटा, अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीजें नीचे फेंक दीं और हाथ धोने जाने लगा तो पहलवान बोले- जरा ठहरो बेटा। मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए और तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़ कर बोले, देखा तुमने। कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया। लेकिन उसने फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिख लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है।

टेंडें

उत्तर प्रदेश में अब शांति

आज उत्तर प्रदेश में कोई अशांति नहीं है, सुडनों पर नज़ाज़ नहीं पड़ी जा रही है, मस्जिदों से माइक्रोफोन की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई गोदव्या नहीं हो रही है, न ही लव जिहाद की कोई घटना घट रही है। - योगी आदित्यनाथ, सीएम, UP

टीएमसी की धारणा

असम में दस साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां के लोग मांसाहारी भोजन खाते हैं तो फिर टीएमसी गंगाल में डब गलत धारणा क्यों फैला रही है कि भाजपा गंगाल में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा देगी? - हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

परिसीमन पर छल

हम महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हैं, लेकिन इस सरकार द्वारा इसे पेश करने का तरीका राजनीतिक रूप से प्रेरित है। हमारी धारणा है कि इस संशोधन को राजनीतिक इर्धिरण के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इसे लागू करें। दूसरा, सरकार परिसीमन पर छल कर रही है। - मल्लिकार्जुन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

कच्चे तेल की कीमतें

आरबीआई के पूर्ववित्तज्ञों के आधार पर, लगता है कि कच्चे तेल की कीमतों में आप आयातक उछाल के दावा होने के बाद ही ब्याज दरों में वृद्धि शुरू होगी। हालांकि, चिंता की बात यह है कि तब तक, जीएस्टी युक्तिरेका के माध्यम से हासिल किया गया न्यून सुधार बेअसर हो सकता है। - स्वामीजी महाराज पंचगणान, उद्यमी

हमारा पता

हरिभूमि कार्यालय

रिंग रोड नं. 2, गौरवपुर, बिलासपुर
फोन: 401050, 271016, फैक्स: 271018
ई-मेल: haribhoomibsp@gmail.com
वेब-साइट: www.haribhoomi.com

छह सौ करोड़ का सीजीएमएससी घोटाला, चार के खिलाफ कोर्ट में पूरक चालान पेश

हरिभूमि न्यूज-रायपुर

छह सौ करोड़ रुपए से ज्यादा के रिजेंट घोटाला में ईओडब्लू तथा एसीबी की टीम ने विशेष न्यायालय में घोटाला में शामिल चार आरोपियों के खिलाफ करीब साढ़े तीन हजार पन्नों का पूरक चालान पेश किया है। जिनके खिलाफ पूरक चालान पेश किया गया है, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 120 बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज है।

जांच एजेंसी ने हरियाणा, पंचकुला स्थित रिकार्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अभिषेक कौशल, रायपुर स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट के प्रोप्राइटर राकेश जैन, रिकार्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट

जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया, उनमें शशांक चोपड़ा के जीजा भी शामिल



लिमिटेड के लाइजनेर तथा शशांक चोपड़ा के जीजा प्रिंस जैन, नवी मुंबई स्थित डायसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मार्केटिंग हेड कुंजल शर्मा के खिलाफ पूरक चालान पेश

किया है। जांच एजेंसी सीजीएमएससी घोटाला में शामिल अब तक 10 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है।

राज्य के आम जनता को निःशुल्क डायग्नोस्टिक जांच उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों, एफआरयू, सीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्र में "हमर लैब" योजना अंतर्गत क्रय किए जाने वाले मेडिकल उपकरण एवं रिजेंट्स की निविदा प्रक्रिया में पूल टेंडरिंग के माध्यम से मोक्षित कॉर्पोरेशन पर निविदा हासिल करने का आरोप है। विवेचना में यह तथ्य सामने आया है कि शशांक

चोपड़ा का जीजा प्रिंस रिकार्ड एंड मेडिकेयर सिस्टम्स के लिये लाइजनिंग का काम करता था।

रिकार्ड्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ने भविष्य में सीजीएमएससी में अपनी सप्लाई चैन मजबूत करने के उद्देश्य से मोक्षित कॉर्पोरेशन को सहयोग किया। तीनों फर्मों के द्वारा अपनी अर्हता सुनिश्चित करने के लिये टेंडर की शर्तों के अनुसार वास्तविक क्षमता से पृथक उत्पादक क्षमता, सर्विस, मेंटेनेंस एवं इंस्टॉलेशन के फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर निविदा में उपयोग किया गया, जिसके लिये प्रिंस कोचर द्वारा समन्वय कार्य किया गया।

प्रतिस्पर्धी कंपनियों को साथ जोड़ा

जांच में सामने आया है कि निविदा प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धी को प्रभावित करने के उद्देश्य से कुछ फर्मों द्वारा आपसी समन्वय और कार्टेलाइजेशन किया गया। इस वजह से टेंडर में यही तीन फर्म शॉर्टलिस्ट हुई थीं, जिनकी वित्तीय दर खोली गई। तीनों पात्र फर्मों द्वारा भरे गए टेंडर में उत्पाद, पैक-साइज, रिजेंट और कंज्यूमेबल्स का विवरण समान पैटर्न में भरा गया। जिन उत्पादों का नाम निविदा दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं था, उन्हें भी तीनों फर्मों द्वारा समान रूप से दर्शाया गया। दर भी समान पैटर्न में कोड किए गए, जिसमें सबसे कम दर मोक्षित द्वारा, उसके बाद आरएमएस तथा श्री शारदा इंस्टीट्यूट द्वारा कोड किया गया।

नए सत्र में प्रदेश में 25 हजार पंप लगाने का केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव

सौर सुजला योजना बंद, 50 हजार आवेदन पेंडिंग, अब पीएम कुसुम योजना में ही लगेंगे सोलर कृषि पंप

हरिभूमि न्यूज- रायपुर

प्रदेश के किसानों को कृषि के लिए सोलर पंप भी लगाने की भाजपा सरकार में 2016 में प्रारंभ की गई सौर सुजला योजना अब बंद हो गई है। इसके स्थान पर अब केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाकर दिए जाएंगे। इसके लिए क्रेडा ने प्रदेश सरकार के माध्यम से नए सत्र के लिए केंद्र सरकार के पास प्रदेश के किसानों के खेतों में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में 25 हजार पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा है। वहां से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद क्रेडा खेतों में पंप लगाने का काम प्रारंभ करेगा। प्रदेश में अब तक एक लाख साठ हजार सोलर पंप लग चुके हैं। अंतिम साल में योजना को बंद करने के कारण महज सात हजार पंप लग पाए हैं। इस समय क्रेडा के पास करीब 50 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। इन आवेदनों का निराकरण केंद्र सरकार से मंजूरी के बाद ही होगा।

प्रदेश में किसान खेतों के लिए कृषि पंप लगाने का काम करते हैं। ज्यादातर कृषि पंप तो बिजली से चलने वाले लगाए जाते हैं। लेकिन प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली की सुविधा न होने पर या किसानों के खेतों के पास बिजली के ट्रांसफार्मर और खंभे न होने के कारण कृषि पंप लगाने के लिए करीब दस साल पहले प्रदेश में भाजपा की रमन सरकार के समय सौर सुजला योजना राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। तब सौर सुजला योजना के माध्यम से सोलर कृषि पंप लगाने का काम किया गया। उसी समय प्रदेश



में बहुत ज्यादा सोलर कृषि पंप लगाए गए।

हर साल लगे 20 हजार पंप

राज्य सरकार ने चूंकि इस योजना का प्रारंभ एक नवंबर 2016 को किया था, इसलिए पहले साल 2016-17 में महज 12 हजार सोलर पंप किसानों के खेतों में लगाए गए। इसके बाद से हर साल प्रदेश सरकार ने 20 हजार के आस-पास सोलर पंप लगाने का काम किया। 2025-26 के लिए भी वैसे तो 20 हजार

सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस बीच फैसला किया गया कि अब केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना में ही कृषि के लिए सोलर पंप लगाने का काम होगा, इसलिए राज्य सरकार की योजना में महज सात हजार पंप ही लग पाए हैं।

अब केंद्र सरकार की योजना में लगेंगे

अब किसानों को सोलर पंप केंद्र सरकार की पीएम कुसुम योजना में लगाकर दिए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के पास 25 हजार पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने पर पंप लगाए जाएंगे। इस योजना में भी किसानों को सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अभी तय नहीं है कि इसमें सब्सिडी कितनी मिलेगी। राज्य सरकार की योजना में महज 10 से 20 हजार पंप लग जाते थे। क्रेडा के अधिकारियों के मुताबिक अब तो सोलर पंप लगाने की लागत कम हो गई है। इस समय तीन एचपी के लिए करीब ढाई लाख और पांच एचपी के लिए तीन लाख दस हजार में लगते हैं। टेंडर के बाद यह लागत और कम हो सकती है।

प्रस्ताव भेजा है

केंद्र सरकार को पीएम कुसुम योजना में प्रदेश में 25 हजार सोलर कृषि पंप लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने पर नए सत्र में पंप लगाने का काम प्रारंभ होगा।

- भूपेंद्र सवनी, अध्यक्ष, क्रेडा

जमीन के उपयोग का ब्योरा अब सीजी जियो पोर्टल पर होगा, परियोजनाओं की प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी

राज्य शासन ने जारी किया आदेश, प्री-एग्जल प्रक्रिया में आएगी तेजी



हरिभूमि न्यूज- रायपुर

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि राज्य में भूमि से संबंधित जानकारी को सीजी जियो पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करना अनिवार्य होगा। इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभागों को भूमि की वास्तविक स्थिति, उपयोग और उपलब्धता की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इससे परियोजनाओं की योजना बनाते समय जमीन से जुड़े विवादों और भ्रम की स्थिति कम होगी। राज्य में भूमि उपयोग और विभिन्न परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सीजी जियो पोर्टल के उपयोग को अनिवार्य करने की दिशा में नए निर्देश जारी किए गए हैं। इससे न केवल प्री-एग्जल प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय भी बेहतर हो सकेगा। नई व्यवस्था के तहत किसी भी औद्योगिक या अन्य परियोजना के प्रस्ताव से पहले 'प्री-एग्जल' प्रक्रिया को

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। जीआईएस आधारित इस प्रणाली से परियोजना क्षेत्र का प्रारंभिक मूल्यांकन तेजी से किया जा सकेगा। इससे निवेशकों को पहले ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रस्तावित भूमि परियोजना के लिए उपयुक्त है या नहीं। विभागों के बीच बेहतर समन्वयनिर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित विभाग, जैसे उद्योग, राजस्व, और आईटी—को पोर्टल के उपयोग में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सभी विभागों को अपने-अपने स्तर पर डेटा अपडेट करने और उसे साझा करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में देरी न हो।

डिजिटल आईडी और ट्रैकिंग सिस्टम लागू

सीजी जियो पोर्टल पर प्रत्येक परियोजना और भूमि से संबंधित जानकारी को एक यूनिक आईडी के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्तावों की ट्रैकिंग आसान होगी और किसी भी स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति तुरंत देखी जा सकेगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी। निवेश को बढ़ावा देने की पहल में राज्य सरकार का उद्देश्य इस डिजिटल व्यवस्था के जरिए निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। भूमि से जुड़ी जटिलताओं और अनुमोदन में देरी अक्सर निवेश में बाधा बनती रही है, लेकिन इस पोर्टल के प्रभावी उपयोग से इन समस्याओं को काफी हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है।

मादक पदार्थ तस्करी में पुलिस के साथ कोर्ट सख्त, तस्कर को 20 साल कैद के साथ पांच लाख जुर्माना

हरिभूमि न्यूज-रायपुर

मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों को अब कोर्ट लंबी सुनवाई की तारीख देने के बजाय उनकी सुनवाई जल्द पूरी कर सजा सुना रही है। इसके साथ ही पुलिस भी तस्करों के खिलाफ नकेल कसने उनकी धर पकड़ करने के साथ ही कोर्ट द्वारा जारी चालान तामिल कराने

पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने एक एसीपी को नोडल अफसर नियुक्त किया है। गंज थाना क्षेत्र में साढ़े चार हजार से ज्यादा प्रतिबंधित नौद की गोली तथा कफ सिरप के साथ गिरफ्तार युवक को विशेष न्यायाधीश किरण थवाईट की कोर्ट ने 20 वर्ष कैद के साथ पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू के अनुसार कोर्ट ने टिकरापारा,

ताजनगर निवासी शोख सरफराज खान उर्फ सोनू को कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। गंज थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पिछले वर्ष 28 जून को घेराबंदी कर प्रतिबंधित टेबलेट के साथ कफ सिरप जब्त किया था। शोख सरफराज ने किसी दूसरे शहर से प्रतिबंधित टेबलेट के साथ कफ सिरप ट्रेन के रास्ते खरीदकर रायपुर बेचने के लिए लाया था।

नारी शक्ति वंदन विधेयक

से देश में खुशी : बजाज

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धन्यवाद देते हुए कहा, इस विधेयक के पेश होने से देशभर में खुशी का माहौल है। श्री बजाज ने विपक्षी दलों से अप्रहंसा किया कि बिना कितने परंतु के इस बिल का समर्थन करें। नारी शक्ति वंदन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होना नए भारत की ऐतिहासिक घटना होगी तथा इससे संसद का गौरव बढ़ेगा। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को मिलने वाला 33% आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिला नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है।

कांग्रेस का जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं : नलिनीश टोकने

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नलिनीश टोकने ने कहा, छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से पूरी तरह कट चुकी कांग्रेस अब केवल कागजी और सोशल मीडिया पर अपनी प्रासंगिकता खोजने की असफल कोशिश कर रही है। श्री टोकने ने कहा, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र-छात्राओं के हित में दोपहर 2:40 बजे अपने आधिकारिक हैंडल से स्कूलों में 20 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी थी, लेकिन आश्रय की बात यह है कि इसके करीब डेढ़ घंटे बाद, शाम 4:05 बजे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज उसी भीषण गर्मी का हवाला देते हुए स्कूलों में छुट्टी की मांग कर रहे हैं।

बेफिक्र जिन्दगी के आगे दर्द क्या चीज़ है ?

डा. ऑर्थो स्ट्रॉंग तेल

Clinically Tested*
*For efficacy and safety.

जोड़ों के दर्द का Specialist

गुठना दर्द, कमर दर्द, कलाई दर्द, कंधा दर्द

10 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों व सत्वों के योग से निर्मित डा. ऑर्थो स्ट्रॉंग तेल जोड़ों के अंदर तक समाकर दर्द को कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें। आयुर्वेदिक होने के कारण इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं लम्बे समय तक बना रहता है।

24x7 Helpline: 78769 77777 | www.drorthooil.com

डा. ऑर्थो
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

हमारी जनगणना हमारा विकास

(जनगणना 2027 का पहला चरण)

स्व-गणना (Self Enumeration) से जुड़े सामान्य प्रश्न और उत्तर (भाग-1)

स्व-गणना क्या है?

स्व-गणना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें आप प्रगणक की प्रतीक्षा किए बिना, स्वयं SE पोर्टल (se.census.gov.in) पर अपने परिवार की जानकारी भर सकते हैं

- क्या स्व-गणना अनिवार्य है? नहीं, यह अतिरिक्त सुविधा है, यदि आप स्व-गणना नहीं करते तो प्रगणक आपके घर आकर जानकारी दर्ज करेगा
- क्या मैं किसी भी भाषा में स्व-गणना कर सकता / सकती हूँ? यह सुविधा हिंदी, अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है
- क्या स्व-गणना के लिए इंटरनेट जरूरी है? हाँ, पोर्टल तक पहुँचने और जानकारी भरने के लिए इंटरनेट आवश्यक है
- क्या मेरी जानकारी सुरक्षित है? हाँ, सभी डेटा सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और सरकारी सर्वरों में संरक्षित है
- SE ID क्या है और इसका उपयोग क्या है? सबमिशन के बाद आपको एक विशिष्ट 11 अंकों की SE ID मिलेगी (SMS / email से), जिसे प्रगणक के आने पर उन्हें दिखाना आवश्यक होगा
- यदि SE ID भूल जाएँ तो क्या करें? पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से SE ID पुनः प्राप्त की जा सकती है
- क्या स्व-गणना के बाद भी प्रगणक आएगा? हाँ, प्रगणक आपके घर आएगा और SE ID के आधार पर जानकारी की पुष्टि करेगा
- क्या मुझे कोई दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता है? नहीं, किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है
- क्या पोर्टल पर सहायता उपलब्ध है? हाँ, पोर्टल पर, यूजर गाइड, फ्लोचार्ट, व्हाट्सएप वीडियो, FAQs और टूलटिप्स के रूप में सहायता उपलब्ध है

टोल फ्री - 1855

चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी

CensusIndia2027

इस हफ्ते से संपर्क क्रांति और अमरकंटक में घर से नहीं लाना होगा चादर-कंबल, 70 रुपए में मिलेगा बेडरोल

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब घर से चादर और कंबल लेकर सफर करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे प्रशासन अब एसी कोच की तर्ज पर स्लीपर में भी बेडरोल की सुविधा शुरू करने का हवा है। इसे लेकर रायपुर मंडल ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उम्मीद है कि इसी हफ्ते से यह सुविधा यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि स्लीपर कोच में दिए जाने वाले चादर, तकिया और कंबल बेहद अच्छी गुणवत्ता के होंगे। इनका रंग थर्ड एसी में मिलने वाले बेडरोल से अलग रखा गया है, ताकि चोरी होने या दोनों कोच के बेडरोल आपस में मिलने की आशंका न रहे। रेलवे ने इस सुविधा का संचालन करने के लिए एक एजेंसी के साथ 4 से 6 लाख रुपये में अनुबंध किया है। हरिभूमि की टीम ने रेलवे की इस नई सुविधा और तैयारियों का जायजा भी लिया। बता दें कि शुरूआती चरण में यह सुविधा रायपुर मंडल को दो प्रमुख ट्रेनों संपर्क क्रांति और अमरकंटक एक्सप्रेस में शुरू की जा रही है।

अच्छी गुणवत्ता के होंगे चादर-तकिया, थर्ड एसी से अलग होगा रंग ताकि न हो मिक्सिंग की समस्या



रेलवे प्रशासन ने तय किया है कि एजेंसी को कोच के अंदर बेडरोल रखने के लिए दो सीटें आवंटित की जाएंगी और इन दोनों सीटों का खर्च एजेंसी ही वहन करेगी। एजेंसी ने इसके लिए कोच क्रमांक एस-4 या 3 की डिमांड की है। हालांकि, कोच में बेडरोल रखने को लेकर फिलहाल एक तकनीकी समस्या बनी हुई है।

रायपुर से ट्रेन के प्रस्थान के समय तो एजेंसी को बेडरोल रखने के लिए आसानी से दो सीटें मिल जा रही हैं, लेकिन वापसी के दौरान दिल्ली से संपर्क क्रांति और भोपाल से अमरकंटक के लौटते समय बेडरोल के लिए आरक्षित सीटें मिलने में दिक्कत आ रही है। रेलवे प्रशासन इस समस्या का समाधान करने में जुटा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इसी हफ्ते इस तकनीकी समस्या को सुलझा लिया जाएगा और यात्रियों के लिए यह सुविधाजनक सेवा विधिवत शुरू कर दी जाएगी। इस सुविधा से स्लीपर कोच से दो सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन बेडरोल की सुविधा आसान हो जाएगी। रेलवे प्रशासन मंडल की ट्रेनों में इस सुविधा को लागू करेगा। पहले दो ट्रेनों में शुरू करने के बाद इसे 10 अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में इसे लागू किया जाएगा। इसमें दुर्ग-निजामुद्दीन संपर्क क्रांति, दुर्ग-उधमपुर, निजामुद्दीन-दुर्ग,

उधमपुर-दुर्ग, दुर्ग- उधमपुर, दुर्ग- अजमेर, अजमेर- दुर्ग, दुर्ग-अजमेर, अजमेर-दुर्ग, दुर्ग-भोपाल अमरकंटक, भोपाल-दुर्ग अमरकंटक, दुर्ग नौतनवा, नौतनवा- दुर्ग, दुर्ग-बेतवा, बेतवा-दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग-नौतनवा एक्सप्रेस, नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस, दुर्ग-अंबिकापुर, अंबिकापुर-दुर्ग एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। इस नई सुविधा से स्लीपर कोच में लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। बेडरोल देने से पहले एजेंसी यात्री का पीएनआर और बर्थ क्रमांक नोट करेगी, उसके बाद बेडरोल देगी। बेडरोल रखने के लिए रेलवे, ठेका एजेंसी को प्रत्येक ट्रेन में दो बर्थ देगा।

इस हफ्ते शुरू कर सकते हैं

स्लीपर कोच में बेडरोल के लिए कंपनी से अनुबंध हो चुका है। सबसे पहले दुर्ग-अंबिकापुर और संपर्क क्रांति में लागू किया गया है। तैयारी पूरी है। हम इस हफ्ते यह सुविधा यात्रियों के लिए शुरू कर सकते हैं। - अवधेश कुमार त्रिवेदी, सीनियर डीसीएम रायपुर

एमपी से छत्तीसगढ़ को मिले 2000 करोड़, हकदार बनकर सामने आए पेंशनर

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लंबित लगभग साढ़े 10 हजार करोड़ रुपये की वसूली राशि को लेकर पेंशनरों ने अपनी मांग तेज कर दी है। भारतीय राज्य पेंशनर्स म हास संघ, छत्तीसगढ़ ने कहा, यह राशि मूलतः पेंशनरों के अधिकार की देकर है। अतः मध्यप्रदेश से वसूली में प्राप्त 2000 करोड़ की राशि को राज्य में डीआर एरियर के रूप में पेंशनरों को तुरंत अंतरिम राहत देकर भुगतान करने की मांग की है।

महासंघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव एवं प्रदेश महामंत्री प्रवीण कुमार त्रिवेदी ने जारी बयान में कहा, बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेंशनरों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है। ऐसे में वर्षों से लंबित डीआर एरियर का भुगतान न होना अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि मध्यप्रदेश

से वसूली की जा रही बड़ी राशि का उपयोग पेंशनरों के हित में किया जाए, तो लाखों वरिष्ठ नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें वास्तविक राहत मिल सकेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मध्यप्रदेश से प्राप्त होने वाली राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर उसे पेंशनरों के लंबित 88 माह के डीआर एरियर भुगतान में उपयोग किया जाए, ताकि उन्हें उनका वास्तविक हक मिल सके और महंगाई के इस कठिन समय में राहत प्रदान की जा सके।

जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाए

महासंघ ने यह भी आरोप लगाया कि इतनी बड़ी वित्तीय चूक के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। केवल बैंक को जिम्मेदार ठहराना इस गंभीर मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास प्रतीत होता है। संगठन ने मांग की कि इस पुरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। पदाधिकारियों ने कहा कि महासंघ वर्ष 2018-19 से लगातार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करता रहा है, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

सोलर से रोशन गांवों में भी बिजली की लाइन पहुंचाने की तैयारी

एमडी भीम सिंह कंवर ने किया कोटा वनांचल क्षेत्र के चार गांवों का स्थल निरीक्षण

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

प्रदेश क्षेत्र के वनांचल के गांवों में जहां अब तक सोलर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की गई थी, अब शीघ्र ही मुख्य बिजली लाइन (ग्रिड) से जोड़ा जाएगा। इससे इन गांवों को अस्थाई सोलर व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और नियमित, स्थाई बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसका जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।



श्री कंवर ने बिलासपुर के कोटा वनांचल क्षेत्र के चार गांवों का स्थल निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का आकलन किया तथा आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित बिजली अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते कोटा वनांचल में स्थित सरगोड़, झुइहवा, चिचवा डबरी एवं परसापानी गांवों में पहले सोलर प्लांट के जरिए बिजली पहुंचाई गई थी। किंतु अब बिजली विभाग ने इन गांवों को मुख्य ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे ग्रामीणों को निर्बाध एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की टीम ने गांवों में पहुंचकर सर्वे एवं तकनीकी निरीक्षण किया। इस दौरान एमडी श्री कंवर ने कहा, सोलर व्यवस्था एक अस्थाई समाधान था, लेकिन अब इन गांवों को मुख्य बिजली लाइन से जोड़कर स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीणों ने भी इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अब उन्हें सीमित सोलर बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे पंखा, टीवी, मोटर जैसे उपकरणों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। चूंकि ये गांव घने जंगलों से घिरे हुए हैं, अतः वहां तक बिजली लाइन खींचने के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की भी आवश्यकता होगी। इस संबंध में अधिकारियों ने श्री कंवर को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने वन विभाग से क्लीयरेंस प्राप्त करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि चारों गांवों की विद्युतीकरण में किसी प्रकार की बाधा न आए। निरीक्षण के दौरान विद्युत कंपनी के अधीक्षण अभियंता पाण्डेय, कोटा ईई राजेन्द्र गौड़ सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (CIVIL) AU & PC, CSPGCL, Raipur. SHORT TERM E-TENDER NOTICE. Online bids are invited through CSPCL e-bidding system (SAP SRM) from eligible bidders fulfilling the eligibility criteria as mentioned below and having experience in Govt./Public Sector Undertaking/Local bodies/Power Generating Companies in India only for the following work:-

Sl. No.	Tender Specification No.	Description	NIT value i/c GST (Rs.)	EMD (Rs.)	Completion period (incl. Rainy season)	RfX No.
1	CEC/AU&PC/HTPS-KW/W/2025/146	Ash Utilization by disposal of ash in eco-friendly manner from Ash Dyke Dindolbhatta of 1x500 MW Extn., HTPS, CSPGCL Korba West for land development of Bilaspur Municipal Corporation land parcels at Bilaspur Sendori for Proposed CBG Plant and MRF sites (PART-I).	488.21 Lacs	4,88,300/-	03 Months	81000 50632
2	CEC/AU&PC/HTPS-KW/W/2025/147	Ash Utilization by disposal of ash in eco-friendly manner from Ash Dyke Jhabu of 4x210 MW, HTPS, CSPGCL Korba West for land development of Bilaspur Municipal Corporation land parcels at Bilaspur Sendori for Proposed CBG Plant and MRF sites (PART-II).	438.24 Lacs	4,38,300/-	03 Months	81000 50640

Cost of tender form is Rs. 1180/- (Rs.1000/- + 18% GST). The due date & time for submission of bids, Tender Cost & EMD is 06.05.2026 (up to 15:00 Hrs) and bid opening date (Techno commercial bids) is 08.05.2026 (up to 16:00) Hrs respectively. The tender document can be viewed and downloaded online from our e-bidding portal https://ebidding.cspcl.co.in:50724/irj/portal. Note:- (i) The L-1 bidder shall be decided on overall cost to company basis including GST.(ii) In case, the rate quoted by the bidder is on abnormally lower side, a performance guarantee @5% of contract value i/c GST in addition to Security Deposit shall have to be deposited by the bidder.(iii) Maintenance period for the work shall be 12 (Twelve) Months.(iv) Subletting of contract will not be allowed. Chief Engineer (Civil) AU & PC, CSPGCL, Raipur

राजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99. भारत का राजपत्र The Gazette of India. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948. NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2026

का.आ. 1782(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 642(अ) तारीख 06 फरवरी 2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के गांव-सेंदरी, गतौरी, तालुक-बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया रा.स. 130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 तक के भूखण्ड के निर्माण (सौदा करने/चार लेन का बनाना आदि), अनुसंधान, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "13.02.2026" को "हरिभूमि" और "द सेन्ट्रल क्रॉनिकल" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वांक प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आधुनिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के गांव-सेंदरी, गतौरी, तालुक-बिलासपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया रा.स.130) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 53.300 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अध्या संरचना रहित विवरण।

2507 GI/2026. जिला : बिलासपुर फाइल नंबर: NHA/LA/14012/01/Notif.-CG/Bilaspur/3D. शोख अमीन खान, निदेशक. https://egazette.gov.in. प्रकाशन तिथि: 08/04/2026. https://www.gazette.gov.in. https://10.192.209.35

नोट : इस अधिसूचना की वास्तविक प्रति सीएएलए/पीआईए/पीएमयू/आरओ/इंडी के कार्यालय में भी उपलब्ध है और भूमि मालिक वहां भी अधिसूचना देख सकते हैं।

राजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD.No. D. L.-33004/99. भारत का राजपत्र The Gazette of India. सौ.जी.-सौ.जी. अ.-11042026-271738. CG-CG-E-11042026-271738. EXTRAORDINARY. भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड (ii). PART II-Section 3-Sub-section (ii). प्राधिकार से प्रकाशित. PUBLISHED BY AUTHORITY.

सं.1770] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2026/चैत्र 20, 1948. No.1770] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2026/CHAITRA 20, 1948

रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) अधिसूचना बिलासपुर, 10 अप्रैल, 2026. रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड.) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 1839 (अ). - केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात् (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 939 (अ) 20 फरवरी 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् भालुमुड़ा से गारेपेलमा नई स्पर लाईन परियोजना (17 किमी) के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना संख्यांक का. आ. 939 (अ) 20 फरवरी 2026 का सार दैनिक समाचार पत्र, इम्पाट टाइम्स (हिन्दी), रायगढ़ संस्करण, 27.02.2026 एवं दैनिक भास्कर (हिन्दी), बिलासपुर संस्करण, 27.02.2026 में प्रकाशित किया गया था; और निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) के अनुसार उन पर विचार किया गया और उनका निराकरण किया गया; और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है; अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20 (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है; और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ड.) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप से निहित हो जाएगी।

ग्राम का नाम :- मिल्पारा, तहसील - तमनार, जिला रायगढ़ (छ. ग.)

क्र. सं.	खसरा नं.	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि स्वामी का नाम
1	108/2 244 308/1 345/1 347/1	0.209 0.065 0.050 0.344 0.110	निजी	कृषि	परसलाल पिता जनकराम, धनसिंह पिता रघुनाथ, शिवकुमार पिता रघुनाथ, दीपमाला पति नीलमणि, प्रेमा पिता नीलमणि, ना बा हंशा पिता नीलमणि, ना बा हर्ष पिता नीलमणि, सेवती पिता रघुनाथ डोलकुंवर पिता रघुनाथ, सुखमती पिता जीवनलाल हारावती पिता जीवनलाल जाति- अचरिया नि. ग्राम भूमिस्वामी
2	246/3	0.045	निजी	कृषि	अशोक वो मापुरी वो तारा पिता मोहितराम केवरावती बेवा मोहितराम पिता चैतराम पिता जीवधन जाति- अचरिया सा देह भूमिस्वामी
3	143/2	0.028	निजी	कृषि	धरम सिंह पिता मुनु जाति-रावत सा देह भूमिस्वामी
4	153/7	0.101	निजी	कृषि	हरिशचंद्र पिता तिलकराम जाति-कलंगा सा देह भूमिस्वामी
5	146/7	0.045	निजी	कृषि	बोधन पिता चमार सिंह जाति-कलंगा सा देह वन अधिकार पत्रकधारी

कुल योग :- 0.977 हे. [फा. सं. सी.ए.ओ./सि/ बी.एस.पी / ईस्ट रेल कॉरिडोर/20E] मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS (South East Central Railway) NOTIFICATION Bilaspur, the 10th April, 2026. NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 1839(E). - Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board) number S.O. 939 (E), dated the 20.02.2026, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely BHALUMUDA to GAREPELMA (17 km.) in the state of Chattisgarh. And, whereas the substance of the said notification No. 939 (E) was published in the daily Newspapers, Ispat Times (Hindi) Raigarh Edition on 27.02.2026 and Dainik Bhaskar (Hindi) Bilaspur Edition on 27.02.2026.

And whereas. No objections were received within the set time period and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said act;

And, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government:

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by subsection (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of subsection (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Name of Village: - Milupara, Tahsil:- Tamnar, Dist:- Raigarh

Sl. No.	Khasra No.	Area of Acquired Land	Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner
1.	108/2 244 308/1 345/1 347/1	0.209 0.065 0.050 0.344 0.110	Pvt.	Agri.	Parasral father Janakram. Dhansingh father Raghunath, Shivkumar father Raghunath, Deepmala husband Neelmadi. Prema father Neelmadi. Na. Ba. Hansha father Neelmadi. Na. Ba. Harsh father Neelmadi, Sevii father Raghunath, Indu father Raghunath, Dolkunwar father Raghunath, Sukhmati father Jeevanlal, Harawati father Jeevanlal. Cast- aghariya ni. village bhoomiswami.
2.	246/3	0.045	Pvt.	Agri.	Ashok wo Madhuri wo Tara father Mohitram, Kevrawati bawa Mohitram father Chaitram father Jeeewardhan. Cast- Aghariya sa deh bhoomiswami.
3.	143/2	0.028	Pvt.	Agri.	Dharam singh father munu cast- Rawat sa deh bhoomiswami.
4.	153/7	0.101	Pvt.	Agri.	Harisanchandra father Tilakram cast- Kalanga sa deh bhoomiswami
5.	146/7	0.045	Pvt.	Agri.	Bodhan father Chamar singh cast- Kalanga sa deh van adhikar patrakdhari.

Total 0-977 Hectare [F. No. CAO/C/BSP/East Rail Corridor/20E] MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer (Con.)

खबर संक्षेप

एमएड-बीएड विभागीय प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एमएड और बीएड विभागीय प्रशिक्षण के लिए प्रवेश प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 से एससीईआरटी की वेबसाइट पर शुरू हो गई है। पात्र शिक्षक ऑनलाइन आवेदन इस लिंक के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें चयन वक्रिका के आधार पर होगा। शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकरनगर के प्राचार्य ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग संवर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी, पंचायत विकास विभाग, नगरीय नियोजन विभाग से प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक, शिक्षक, प्रधानपाठक प्राथमिक शाला एवं अपने आवेदन को यथास्थिति संबंधित महाविद्यालय में 7 मई तक जमा करेंगे। तीनों विभाग के अर्थी एमएड, बीएड प्रशिक्षण के लिए एससीईआरटी की साइट से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर आवेदन को हार्डकॉपी में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर अपने धावार्थ से अप्रेषित 15 से 30 अप्रैल तक केवल ऑनलाइन भरेगा। इस भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट कराकर 7 मई तक अपने संबंधित विद्यालय में जमा करेंगे।

23 गांव में नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुनर्गठन

रायपुर। सहकारिता के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रायपुर जिले में 23 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पीएसीएस) का पुनर्गठन किया गया है। इन नवीन समितियों का गठन कुकेरा, पथरी, मांढर, पवनी, परसतगई, मालीडीह, बेजोडरडीह, बनरसी, चरौदा, सोना, बकतरा, हसदा, उमारपोटी, भरेंगा, अकोलीकला, अमेटी, तोडगांव, समोदा, भुरसुदा, भूमिया, मुनगी एवं तुलसी में हुआ है। नवीन गठित समितियों के माध्यम से किसानों को अब खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि ऋण एवं अन्य आवश्यक सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही सुलभ हो सकेंगी, साथ ही किसान अपनी उपज का भंडारण एवं विपणन भी इन समितियों के माध्यम से कर सकेंगे। इससे रायपुर उचित कीमत मिलेगी।

धधका रायपुर, 43 डिग्री का टार्चर

रायपुर। प्रदेश के मध्य क्षेत्र में आगामी तीन दिन भीषण गर्मी वाले रहेंगे। मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, मध्य क्षेत्र अर्थात रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में इस दौरान ग्रीष्म लहर चलने की आशंका है। गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक है। इसी तरह न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक 27.9 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक गर्म राजनांदांव रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.5

जिलों में प्रभारी महामंत्री नहीं, कार्यालय प्रभारी बनाए जाएंगे
कांग्रेस जिला अध्यक्षों को कार्यकारिणी बनाने 21 अप्रैल तक की मोहलत

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलों में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के तीन माह के अंदर कार्यकारिणी तैयार करने के निर्देश जारी किए गए थे। प्रदेश के 41 संगठन जिलों में 35 ने अपनी कार्यकारिणी की सूची पीसीसी को सौंप दी थी। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर के शहर व ग्रामीण जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी। उन्हें 15 अप्रैल तक सूची जारी करने कहा गया था। अंतिम तारीख बीतने के बाद इनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई, अब उन्हें 21 अप्रैल तक कार्यकारिणी तैयार कर जमा करने कहा गया है। बताया गया है कि प्रदेश संगठन के तहत 80 प्रतिशत से अधिक काम हो गया है, आने वाले दो तीन दिनों में शेष कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।

बताया जा रहा है कि जिला कार्यकारिणी के गठन में एआईसीसी के निर्देशानुसार केवल 31 ही सदस्यों की अनुमति मिली है, जिसके चलते ही कार्यकारिणी गठन में लेटलतफी सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और स्थानीय वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि बड़े विधानसभा वाले जिलों में सिर्फ 31 सदस्यों की कार्यकारिणी गठन करना मुश्किल है। संगठन के नेताओं में इससे नाराजगी बढ़ेगी, इसलिए लगभग आधा दर्जन जिलों में कार्यकारिणी गठन को रोककर रखा गया है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि कई जिलों में कार्यकारिणी गठन का

एआईसीसी से कार्यकारिणी के लिए 31 सदस्यों की मिली अनुमति, बड़े जिलों में 51 की मांग



पंच स्थानीय वरिष्ठ नेताओं के खींचतान की वजह से भी फंसा हुआ है। एआईसीसी ने जिला कार्यकारिणी गठन की संख्या 51 से घटाकर 31 सदस्यों तक सीमित कर दी है।

पीसीसी के जिलों में प्रभारी महामंत्री के पद को कार्यालय प्रभारी पद किए जाने के निर्देश के बाद जिला अध्यक्षों में नाराजगी उभरकर सामने आई है। बताया गया कि कांग्रेस के अधिकांश जिलों में पदाधिकारियों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। परंपरागत रूप से जिलों में महामंत्रियों में से एक की प्रभारी महामंत्री बनाया जाता रहा है, ताकि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में

संगठन का कामकाज सुचारु रूप से चलता रहे। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह ने सभी जिलों को पत्र जारी कर प्रभारी महामंत्री के स्थान पर कार्यालय प्रभारी बनाने के निर्देश दिए हैं।

इस निर्देश पर कई जिला अध्यक्षों ने आपत्ति जताई है और अलग-अलग स्तर पर विरोध भी दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि दुर्ग, और रायपुर संभाग के दो-तीन जिला अध्यक्षों ने इस सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भूपेश बघेल से मिलकर शिकायत भी की है। ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों को लेकर भी जिला अध्यक्षों में असंतोष बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ बिंदुओं पर पहले भी शिकायतें की जा चुकी हैं और जब जल्द ही सचिन पायलट से मुलाकात कर कई मुद्दों पर सामूहिक रूप से बात खी जा सकती है। मलकीत सिंह गूंदू ने कहा कि जिलों में प्रभारी महामंत्री का कोई अधिकृत पद नहीं होता, और गलत तरीके से प्रभार दिए जा रहे थे, इसे दुरुस्त करते हुए कार्यालय प्रभारी बनाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर उन्हें कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश के सिर्फ एक जिले से उठ पाया धान, अभी भी सवा चार लाख टन जमा है उपार्जन केंद्रों में, सूखत का खतरा बढ़ा

हरिभूमि न्यूज: रायपुर

छत्तीसगढ़ में पिछले साल नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी के बाद से लेकर इस साल अप्रैल का आधा महीना गुजरने के बाद भी उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव नहीं हो पाया है। हालत ये है कि राज्य के 33 में से केवल एक जिले का ही पूरा धान उठ पाया है। इधर मौसम की तपिश बढ़कर 40 सेंटीग्रेड से उपर तक जा पहुंची है, जाहिर है भीषण गरमी से धान सूखने से वजन कम होगा और उसकी भरपाई सोसाइटी प्रबंधकों के जिम्मे होगी।

राज्य में पिछले साल 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई थी, जो जनवरी 2026 तक जारी रही। कायदे से खरीदी पूरी होने के बाद या उसके बाद के दिनों तक पूरा धान उपार्जन केंद्रों से उठा लिया जाना था, लेकिन सरकार और प्रशासन यह काम अब तक पूरा नहीं कर पाया है। सरकार ने 141 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, लेकिन इस धान में से सवा चार लाख मीट्रिक टन धान अब भी राज्य के 32 जिलों के उपार्जन केंद्रों में जमा है। केवल कोरबा जिले से ही पूरा धान उठाया जा सका है।

इधर राज्य के उपार्जन केंद्रों में धान का हिसाब-किताब निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरिभूमि को मिली जानकारी के अनुसार

राज्य के 32 जिलों की सोसाइटियों में जमा है धान, सैकड़ों सोसाइटियों में अभी हिसाब पूरा होना है बाकी



रायपुर जिले के अभनपुर और आरंग क्षेत्र की कई सोसाइटियों में धान की मात्रा में कमी की जानकारी सामने आई है। इसी क्रम में धमतरी

जिले की सोसाइटियों में करीब 3 हजार क्विंटल धान का शॉर्टेज सामने आ चुका है। बताया गया है कि कई सोसाइटियों अभी भी कह रही हैं कि उनको यहां धान का स्टॉक है, इस पूरा धान का परिवहन होने के बाद हिसाब-किताब करना चाहिए। यह भी पता लगा है कि सरकार ने अतिशेष धान की नीलामी करनी है, इसलिए भी उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव फिलहाल रोक दिया गया है, नीलामी होने के बाद खरीदार खुद धान उठाकर ले जाएंगे।

सूखत का खतरा प्रबंधकों के लिए

इधर राज्य में सोसाइटियों के प्रबंधकों और धान खरीदी के प्रभारियों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ती जा रही है कि धान में सूखत या शॉर्टेज की कीमत उनसे वसूली जाएगी। पिछले वर्ष भी यह देखा गया है कि जिन सोसाइटियों में शॉर्टेज आया है, वहां डीएमओ ने निर्देश दिए कि प्रबंधक या खरीदी प्रभारी शॉर्टेज का बराबर धान जमा कराएं, या उसकी कीमत अदा करें, यह दोनों काम न करने वालों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवाई गई थी। कई सोसाइटियों के लोगों को फरार होने की नौबत भी आई, यह मामला फिलहाल बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित है। इसी प्रकार की नौबत एक बार फिर 2025-26 के खरीफ सीजन में बनती नजर आ रही है।

सहायक शिक्षक के 2292 पदों के लिए विज्ञापन जारी

परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित, व्याप्त लेगा परीक्षा



हरिभूमि न्यूज : रायपुर

सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा प्रदेश के विद्यालयों में सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हुए प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जबकि शिक्षक और व्याख्याता पदों के लिए अभी इंतजार

करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। इन पदों में से 795 पद ई-संवर्ग की शालाओं तथा 1497 पद टी-संवर्ग की शालाओं में भरे जाएंगे। उक्त पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तें भी निर्धारित कर दी गई हैं।

व्याख्याता एवं शिक्षक भर्ती के लिए पृथक विज्ञापन

लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक अशोक नारायण बंजारा ने बताया, विस्तृत विज्ञापन छत्तीसगढ़ व्यापक की वेबसाइट एवं स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम भी व्यापक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इन पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यापक द्वारा किया जाएगा, जिसकी संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि संबंधी जानकारी व्यापक द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। व्याख्याता एवं शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए पृथक से विज्ञापन भी जारी किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनी)

बिजली बंद की सूचना
समाननीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है, कि वितरण केन्द्र लगाव अंतर्गत विभिन्न वितरण केन्द्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु लगाव एवं दरिमा, महामाया अंबिकापुर उपकेन्द्र एवं 11 के.व्ही फीडरों में विद्युत लार्डनों एवं उपकरणों का ग्री मानसूर हेतु आवश्यक अनुरक्षण एवं रखरखाव कार्य कराया जाना है, जिसके लिए लगाव वितरण केन्द्र अधीनस्थ समस्त उपकेन्द्र एवं विभिन्न फीडरों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी जिसके लिए निम्नानुसार तिथि एवं समय निर्धारित है:-

क्र.	दिनांक	समय	उपकेन्द्र	11 के.व्ही. फीडर	विद्युत आपूर्ति हेतु प्रभावित क्षेत्र
01	18.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. लगाव फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली 11 के.व्ही. लगाव फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
02	19.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. चोरकीडीह फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली 11 के.व्ही. चोरकीडीह फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
03	20.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. बटवाही फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली 11 के.व्ही. बटवाही फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
04	21.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. सिलसिला प्लांट फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली 11 के.व्ही. सिलसिला फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
05	22.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	33/11 के.व्ही. रघुनाथपुर (ग्रामीण) फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली समस्त 11 के.व्ही. फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
06	23.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. रघुनाथपुर (टाउन) फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली 11 के.व्ही.
07	24.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव	11 के.व्ही. कोट-गंगपुर फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र लगाव से निकलने वाली समस्त 11 के.व्ही. कोट-गंगपुर फीडर से संबंधित समस्त ग्राम।
08	25.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही सबस्टेशन दरिमा	11 के.व्ही. कज्जी फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र दरिमा से निकलने वाली समस्त 11 के.व्ही. कज्जी फीडर से संबंधित समस्त ग्राम
09	26.04.2026	प्रातः 09.00 से दोपहर 03.00 बजे तक	33/11 के.व्ही सबस्टेशन महामाया अंबिकापुर	11 के.व्ही. फिल्टर प्लांट फीडर	33/11 के.व्ही उपकेन्द्र महामाया अंबिकापुर से निकलने वाली समस्त 11 के.व्ही. फिल्टर प्लांट फीडर से संबंधित समस्त ग्राम

नोट- आवश्यकतानुसार समयावधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है।
- स्वहित एवं राष्ट्रहित में उर्जा बचाव -
- विद्युत चोरी दण्डनीय अपराध है -

कार्यालय यंत्री (सां/स) संभाग
छ.स्ट.पॉ.डि.कं.लिमि.अंबिकापुर

कार्यालय नगर पंचायत घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
Email ID-cmogharghoda@gmail.com Pin-496111

क्रमांक/63/न.पं./ लो.नि.वि./2025-26 **मैनूअल पद्धति प्रथम निविदा सूचना** घरघोड़ा, दिनांक 13/04/2026

नगर पंचायत, घरघोड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासन मद/अधोसंरचना मद/जोनल कार्य अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत टेकदारों से प्रवर्तित रोड/बिल्डिंग SOR 2025/इलेक्ट्रिकल 2020/ दर पर नियम / शर्त अनुसार निम्नलिखित कार्य के लिये इच्छुक फर्म या अधिकृत विक्रेता/निर्माणकर्ताओं/प्रदायकताओं को निम्नलिखित वस्तुओं/ सेवाओं की आपूर्ति/कार्य हेतु प्रारंभ बंद निविदाएं अ. ब. स में पंजीकृत अथवा स्पेड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है :-

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : 05/05/2026 अपराह्न 4:00 बजे तक
2. निविदा प्रपत्र प्रदाय करने की तिथि एवं समय : 08/05/2026 अपराह्न 4:00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय : 12/05/2026 अपराह्न 4:00 बजे तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 13/05/2026 अपराह्न 4:30 बजे तक

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रु. लाख	अमानत राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.
1	वार्ड क्र. 01 में हीरा लाल घर से नाला मार्ग की ओर सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	5.01	5000	750
2	वार्ड क्र. 03 में रेशम घर से अघन घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	3.75	4000	750
3	वार्ड क्र. 04 व 05 में पिट्टू बंसे घर से राजू साहू घर तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	8.33	8500	750
4	वार्ड क्र. 08 में बिजली ऑफिस के पीछे से मेन रोड तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	9.94	10000	750
5	वार्ड क्र. 09 में मुक्तिधाम दाह स्थल तक सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	4.32	4500	750
6	वार्ड क्र. 09 में बस स्टैण्ड में रोड निर्माण कार्य।	5.85	6000	750
7	वार्ड क्र. 11 में डॉ. दिलीप गुप्ता घर से जुगनू चौक की ओर आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	2.88	3000	750
8	वार्ड क्र. 13 में मुख्य मार्ग से बाबू टाकुर घर तक बाथवे निर्माण कार्य।	5.72	6000	750
9	वार्ड क्र. 15 में किरोड़ी शर्मा होटल के पीछे से शंकर मंदिर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6.25	6500	750
10	वार्ड क्र. 04 में अम्बेडकर चौक से ईश्वर लहरे घर तक बी.टी. रोड निर्माण कार्य।	8.33	8500	750
11	वार्ड क्र. 07 में मेन रोड से कोल्हू घर तक बाथवे निर्माण कार्य।	1.95	2000	750
12	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जोनल कार्य वार्ड क्र. 01 से 07 तक रोड एस.ओ.आर एवं बिलडिंग एस.ओ.आर निर्माण कार्य।	9.50	9500	750
13	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु जोनल कार्य वार्ड क्र. 08 से 15 तक रोड एस.ओ.आर एवं बिलडिंग एस.ओ.आर निर्माण कार्य।	9.50	9500	750

1. निविदा की अन्य नियम शर्त कार्यालयीन दिवस व समय में कार्यालय से अवलोकन किया जा सकता है।
2. उक्त तिथियों में अवकाश होने की स्थिति में कार्यवाही आगामी कार्य दिवस पर किया जावेगा एवं आवेदन शुल्क 100/- रसीद के माध्यम से लिया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत घरघोड़ा

एनएमडीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
“खनिज भवन”, 10-3-311/ए, केसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद-500028
कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) - L13100TG1958GO1001674

कार्य प्रभाग अनुबंध विभाग

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक "नवरत्न" सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एनएमडीसी लिमिटेड, निम्नलिखित कार्यों के लिए अनुभवी घरेलू बोलोदाताओं से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित करती है। विस्तृत एनआईटी और बोली दस्तावेजों की प्राथमिक तिथियां भी नीचे दी गई हैं:

क्र. सं.	कार्य का नाम	टीई क्रमांक [एमएसटीसी संदर्भ क्रमांक]	बोली दस्तावेज देखने/डाउनलोड करने की तिथि (से-तक)	बोली-पूर्व बैठक की तारीखें
1.	बावेली, छत्तीसगढ़, भारत में स्थित डिपॉजिट 5 की क्षमता विस्तार हेतु 10 मीट्रिक टन प्रति वर्ष अयस्क पैराई, स्क्रीनिंग, परिवहन और संबंधित सेवाओं एवं अवसंरचना सुविधाओं के लिए- पैकेज बीई-1ए	एचओ (अनुबंध) / बीई/ पैकेज -01ए/ डिप. 5/2026/316 दिनांक 16.04.2026 [एनएमडीसी/प्रधान कार्यालय/अनुबंध/3/26-27/ ईटी/49]	16-04-2026 से 15-05-2026 तक	27/04/2026 & 08/05/2026
2.	बावेली, छत्तीसगढ़, भारत में 5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) भंडार-10 और 3 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) भंडार-11ए लौह अयस्क पैराई, स्क्रीनिंग, परिवहन और क्षमता विस्तार के लिए संबंधित सेवाएं और अवसंरचना सुविधाएं- पैकेज बीई-1बी	एचओ (अनुबंध)/बीई/पैकेज -01बी/ डिप. 10&11/ए/2026/319 दिनांक 16.04.2026 [एनएमडीसी/प्रधान कार्यालय/अनुबंध/4/26-27/ईटी/50]	16-04-2026 से 15-05-2026 तक	27/04/2026 & 08/05/2026
3.	बावेली, छत्तीसगढ़, भारत में क्षमता विस्तार के लिए डाउनहिल कचरॉन सिस्टम, स्क्रीनिंग प्लांट, स्टॉकपाइल, वाई उपकरण, रैपिड टैगन लॉडिंग सिस्टम और संबंधित सेवाएं- पैकेज संख्या बीई-01सी	एचओ (अनुबंध)/बीई/पैकेज-01सी /बीसीएच/ 2026 / 320 दिनांक 16.04.2026 [एनएमडीसी/प्रधान कार्यालय/अनुबंध/5/26-27/ईटी/51]	16-04-2026 से 15-05-2026 तक	27/04/2026 & 08/05/2026

विस्तृत एनआईटी और बोली दस्तावेज निम्नलिखित वेबसाइट लिंक से देखें और/या डाउनलोड किए जा सकते हैं:

1. एनएमडीसी वेबसाइट: <http://www.nmdc.co.in>
 2. केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) <http://www.eprocure.gov.in/epublish/app>
 3. एनएमडीसी पोर्टल-<https://www.mstcecommerce.com/eproc/>
- एमएसटीसी पोर्टल से बोली दस्तावेज प्राप्त करने के लिए, बोलोदाता को एनएमडीसी वेबसाइट लिंक <https://www.mstcecommerce.com/eproc/> पर जाना होगा और **उपपर दी गई तालिका में उल्लिखित निविदा कार्यक्रम संख्या को खोजना होगा।**
- प्री-बिड मीटिंग एनएमडीसी के कार्यालय में बिड डेटा शीट (बीडीएस) के खंड 5 के अंतर्गत क्रमांक 15 में दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलोदाताओं से अनुरोध है कि वे एनएमडीसी लिमिटेड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपनी बोलियां जमा करें। ऑनलाइन बोली जमा करने का विवरण एनआईटी में दिया गया है। बोलोदाताओं को ध्यान रखना है कि बोली प्रकाश के लिए एनएमडीसी की वेबसाइट/सीपीपी पोर्टल/एमएसटीसी वेबसाइट पर नियमित रूप से जाना आवश्यक है और उचित रूप से जारी निम्नलिखित से संपर्क किया जा सकता है:

- 1) श्री एनएमएसएन मूर्ति, वरिष्ठ महाप्रबंधक प्रभारी (एनएमडीसी वित्तार परिरोजना), एमईकॉन लिमिटेड, रांची, दूरभाष संख्या: +91-9431708649, ईमेल: murthy_mssn@meconlimited.co.in
- 2) वरिष्ठ प्रबंधक (ई/अं)/बिड, एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद, दूरभाष संख्या: +91-040-23533536, ईमेल: contracts@nmdc.co.in

कृते-एनएमडीसी लिमिटेड
कार्यकारी निदेशक, (कार्य)


प्रथम पृष्ठ का शेष

मोदी की गारंटी…

संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भी इसका विरोध करनेगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोकसभा में बोलते हुए मोदी ने कहा कि हम सब भाग्यवान हैं कि ऐसे महत्त्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का अवसर मिल रहा है। लोकसभा में चर्चा करने और पारित करने के लिए संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और परिशीलन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किए गए।

लोकसभा में महिला आरक्षण और परिशीलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप इसका विरोध करने तो स्वामाविक है कि इसका मुझे राजनीतिक लाभ होगा लेकिन साथ चलने को किसी को भी नहीं होगा। इसलिए हमें केडिट नहीं चाहिए। जैसे ही यह पारित हो जाए मैं विज्ञापन देकर सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूँ। फ्रेडिट आप ले लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय समाज की मन:स्थिति और नेतृत्व क्षमता उस पल को कैचर करके एक राष्ट्र की अमनात और धरोहर बना देती है। संसदीय इतिहास में आज ऐसा ही एक पल है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण और परिशीलन पर कहा कि हम किसी क्षम में न रहे, हम किसी अहंकार में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को कुछ दे रहे हैं। यह उसका हक है। हमने कई दशकों से उसे रोक़ा है, आज उसका प्रायश्चित करके हमारे लिए उस पाप में से मुक्ति पाने का अवसर है। संसद की इस तीन दिवसीय बैठक के दौरान नारी शक्ति दबन अधिनियम (महिला आरक्षण कानून) में संशोधन कर इसे 2029 तक लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है। संसद के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

महिलाओं की उम्मीदवाजी कितनी एडीआर की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का जो विश्लेषण किया गया था, उसके मुताबिक 2024 में कुल 8,360 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। इनमें से महज 800 महिलाएं थीं। यानी कुल 9.60 फीसदी। इतना ही नहीं 543 लोकसभा सीटों में से 152 यानी करीब 28 फीसदी सीटों पर एक भी महिला प्रत्याशी के तौर पर नहीं उतरीं। राष्ट्रीय दलों में भाजपा ने 16 फीसदी महिलाओं को टिकट दिया। इसके बाद कांग्रेस और माकपा (13-13%) और बसपा आठ फीसदी का स्थान रहा। आम आदमी पार्टी ने एक भी महिला उम्मीदवार को

	डॉ. नरेन्द्र अग्रवाल	सुविधाएं
	चर्म एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ	<ul style="list-style-type: none"> लेजर हेयर रिमूवल हाइड्रोफेशियल कार्बन फेशियल कैमिकल पीलिंग रेडियोफ्रीक्वेंसी लैजर नी टैटू
मस्तीनिक : छत्तीसगढ़ कॉलेज के सामने, त्रिविल लॉडज, बैटनबाजार, रायपुर (छ.ग.) समय : सुबह 10:00 से 2:00 बजे तक		
सिटी कोतवाली के पास, छोटापारा रोड, रायपुर (छ.ग.) शाम 5:00 से 8:30 बजे तक, फोन : 0771-2546760, 9300323131		

	श्री साईं केयर हॉस्पिटल	ऑन्कोलॉजी
	डॉक्टर से सेकंड ओपिनियम, बिना किसी फीस हर सामेवार शाम।	कैंसर केयर, डायबिटिक केयर, पाल्सिट्रिय केयर
	फ्री ओपीडी सेवा	मस्तीनिक के उपरोक्त सोमवार
शिव मंदिर के पास, अवंती विहार, तेलीबाधा, रायपुर (छ.ग.) बुक अपॉइंटमेंट : 0771-4020089, 9630067422		

अष्टविनायक हॉस्पिटल	<ul style="list-style-type: none"> प्रसूति बांझपन बच्चों एवं बड़ों के आपरेसन 	<ul style="list-style-type: none"> नवजात सोनोग्राफी अनुभवी डॉक्टरों प्रतिदिन 	<ul style="list-style-type: none"> शिशु रोग आयुष्मान कार्ड अनुभवी डॉक्टरों प्रतिदिन
बच्चों एवं महिलाओं का अस्पताल			
आमा सिवनी, विधानसभा रोड, रायपुर (छ.ग.), 9826182221 9301744425			

डायबिटिज मधुमेह का सर्वोत्तम इलाज – अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई क्यू जाना	डॉ राका शिवहरे	भर्ती सुविधा
मधुमीत डायबिटिज हॉस्पिटल	MBBS, MD FNIC FIPA	उपलब्ध
शिव मंदिर चौक, अवंति विहार, रायपुर, फोन : 0771- 4060929, मो. 7389485756		

epaper- www.haribhoomi.com		Classsified
Email- hbclassified375@gmail.com		

आवश्यकता है	आवश्यकता है –प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कम्पनी में नहर कार्य हेतु कचोरा में सिविल इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर एवं जेसीबी ऑपरेटर, एजाक्स ऑपरेटर की तत्काल आवश्यकता है सम्पर्क करें- अनुभववी बिजली मिश्री (वैतन योग्यता अनुसार) की आवश्यकता है सम्पर्क करें- 9406390898 (40522)
--------------------	---

आवश्यकता है – अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक में महिला कम्प्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है सम्पर्क करें- सुबह 11बजे से रात 8बजे तक, डॉक्टर अग्रवाल एक्स-रे क्लीनिक, सन्तोष लॉज के बगल में, जूनोब्लाडन, बिलासपुर, 7869911052 (40575)

आवश्यकता है – अम्बिकापुर शंकरगढ़ एवं बिलासपुर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कार्य हेतु अनुभवी सुपरवाइजर की आवश्यकता है। वैतन योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें- 9827180841, 6268490010 (40570)

आवश्यकता है – अनुभववी सिविल इंजीनियर (BE Civil) की जो साईट पर काम करा सके, अनुभववी को प्राथमिकता। वैतन योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें- श्री गणेश कंस्ट्रक्शन राजीव प्लाजा बिलासपुर 93019 22223 (40572)

आवश्यकता है –शिवांगी ऑइस्स प्राइवेट लिमिटेड में बॉयलर ऑपरेटर, ऑफिस कार्य हेतु टेली, एमएस एक्सल अनुभववी डाटा एंट्री ऑपरेटर युवक/ युवती चाहिए वैतन योग्यता अनुसार अनुभव 5-7 वर्ष सम्पर्क समय 12बजे से शाम 6बजे तक 93037 90515, 96669365848 (40549)

मौका नहीं दिया था। विधानसभाओं के आंकड़े तैमन राज्‍य और केंद्र शासित प्रदेशों (पूटी) की विधानसभाओं में महिलाओं की उम्मीदवाी 10 फीसदी के करीब रही। इन राज्‍यों के कुल 43,348 उम्मीदवारों में से केवल 4,295 (10%) महिला उम्मीदवार थीं। देश भर के 4,123 विधानसभा क्षेत्रों में से 1,698 (41%) निर्वाचन क्षेत्रों में एक भी महिला उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा। किसी भी राज्‍य में महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत 15% से ज्यादा नहीं रहा। सबसे अधिक महिला उम्मीदवारों का प्रतिशत दिल्ली (14%), ओडिशा (14%) और छत्तीसगढ़ (13%) में देखा गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में भी यह प्रतिशत क्रमशः 13% और 12% रहा। सबसे कम महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी नगालैंड (2%), अरुणाचल प्रदेश (5%) और जम्मू-कश्‍मीर (5%) में रही।

क्या पहले नहीं हुई इसके लिए कोशिशें? 1996 में केंद्र की देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया था, लेकिन बिल पास नहीं हुआ था। 1998-2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कई बार प्रयास किए , लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते बिल पास नहीं हो सका था। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में अटक गया था। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नए संसद भवन में पारित कराया। अब संसद में पेश क्यों हो रहा है? केंद्र सरकार ने संशोधन विधेयक में परिशीलन को साल 2011 की जनगणना से जोड़कर और 2026 के बाद वाली जनगणना की अनिर्धार्य शर्त को हटाकर इसे प्रायः टूट कर दिया है। इसके साथ ही सीटों की संख्या बढ़ाकर इसे राजनीतिक रूप से अधिक स्वीकार्य बनाया गया है ताकि पुरुष सांसदों की सीटें भी न हिनें। कब से लागू होगा? केंद्र सरकार का लक्ष्य महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह लागू करना है। आज संसद के विशेष सत्र में विधेयक पेश कर दिए गए हैं और कल यानी 17 अप्रैल को इन पर वोटिंग होगी।

महिलाओं का राजनीतिक ...

है कि लोकसभा में हो रही चर्चा महिला आरक्षण विधेयक पर ही नहीं है, बल्कि परिशीलन पर भी है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस राजनीति की बू का जिक्र किया, वह इस विधेयक में पूरी तरह घुली हुई है। प्रियांका ने आरोप लगाया कि सरकार यह विधेयक लाई है क्योंकि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को भागीदारी नहीं देना चाहती है।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, अगर प्रधानमंत्री ने यह ऐतिहासिक कदम ईमानदारी से उठाया होता तो पूरा सख्त इसका समर्थन करता। उन्होंने कहा, अगर आप (प्रधानमंत्री) महिलाओं का सम्मान करते हैं तो महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते तथा यह कदम आपके पक्ष और गरिमा के अनुकूल नहीं है।

छत्तीसगढ़ में 28...

चाहिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व न मिलने पर उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया से वंचित रहने का खतरा बताया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और पंचायत-नगर निकायों में लागू आरक्षण का हवाला देते हुए यह

मांग रखी गई थी कि उसी तर्ज पर संसद और विधानसभाओं में भी समावेशी आरक्षण लागू किया जाए।

बॉयलर विस्फोट, वेदांता...

हुइलर गए, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना में गंभीर रूप से घायल 16 श्रमिकों को खरसिया, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इधर इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी कलेक्टर सतती ने दिए हैं। प्रारंभिक जांच के उपरांत उपलब्ध साक्ष्यों एवं तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर घटना में लापरवाही परिलक्षित हुई है। उक्त परिस्थितियों के आधार पर पुलिस अधीक्षक प्रफूल्ल ठाकुर के निर्देश पर वेदांता कंपनी के प्रबंधक देवेन्द्र पटेल सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कार्मियों के प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर थाना डभरा में अपराध क्रमांक 119/2026, धारा 106(1), 289, 3(5) बीएसएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विवेचन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि प्रारंभिक जांच और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कंपनी के निदेशक समेत 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर विस्तृत विवेचन की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उक्त प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल के नेतृत्व में टीम गठित की है। टीम में अनुसन्धानीय अधिकारी पुलिस सुमित गुप्ता, फोरेंसिक अधिकारी सुष्टि सिंह एवं थाना प्रभारी डभरा राजेश पटेल होगें।

कांग्रेस की जांच टीम ने प्लांट पहुंच कर लिया जायजा हाइले में 20 मजदूरों की मौत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जांच टीम बनाई गई है। कांग्रेस का जांच दल 16 अप्रैल को प्लांट पहुंचा। जांच दल के संयोजक पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉं वरुण दास महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज और कई विधायक प्लांट पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर टीम ने स्थिति का जायजा लिया। कांग्रेस जांच दल ने प्लांट और प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा कर घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी ली।

प्रारंभिक जांच में...

उपकरणों के रख-रखाव तथा संचालन संबंधी मानकों का समुचित पालन नहीं किया गया। उपकरणों की देखरेख में लापरवाही एवं संचालन में उपेक्षा के कारण बायलर के दबाव में अनाक उत्तर-चढ़ाव आया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुर्घटना घटी। उपलब्ध साक्ष्यों एवं तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर घटना में लापरवाही परिलक्षित हुई है।

61 नक्सलियों को...

डिफ्यूज करते हुए टीम पहाड़ के उपर चढ़ रही थी। सप्ताह भर ऊपर चढ़ने के बाद पहाड़ के ऊपर पहुंचे। इस दौरान नक्सलियों के साथ कई बार मुठभेड़ हुआ और टीम के साथ तीन नक्सलियों के शव के अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक, लैथ मशीन, डीजल पेट्रोल के कंटेनर व अन्य सामान बरामद किए गए। 8 मई को ऑपरेशन पूरा करने के बाद टीम वापस करेगुना हिल्स से नीचे आ रही थी। पहाड़ से लगभग थोे नीट्टर उत्तरने के दौरान 9 मई को पत्थर के नीचे प्लांट किए गए आईईडी में विनोद का पैर पड़ गया और जोरदार विस्फोट के साथ वह लगभग 10 मीटर दूर जा गिरे। इस हादसे में उनका उनका दाहिना पैर 64 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो गया और उनके दाहिने कान का पर्दा भी फट गया। टीम के अन्य सदस्यों की मदद से उन्हें वापस करेगुना हिल्स के ऊपर ले जाया गया। इसी दौरान एक अन्य आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आए डीआरजी इंतेवाड़ा का जवान संतोष भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। भाई बनसिंग नाग को पुलिस में भर्ती कर अश्रु रसने को पूरा करना ध्येय-राजेन्द्र कुमार नाग ने बताया कि वे मूलतः छिद्राद तहसील के बकुलाघाट ग्राम के रहने वाले हैं। 15 मार्च 2021 को वे सुकुमा जिला बल में भर्ती हुए थे। इसके बाद राजनांदगांव में प्रशिक्षण लेने के बाद 2022 में डीआरजी का हिस्सा

	दर-दाँत (गम पेंट)	
बायो-डेंट गम पेंट, मुंह के छाले, दांत दर्द और जलन में लाभकारी यह आर्युवेदिक दवा है, यह हर्बल दवा 100 प्रतिशत सुरक्षित है		
94060-21769		


शिव मस्सानाशक
शिव मस्सानाशक को 12-15 घंटों तक लगाकर रखेंगे तो यह मस्से को शीघ्र हटा देगा। जब तक मस्सा न हट जाए, रोज 1-2 बार लगाए। यदि लगाने के बाद किसी कारणवश लेप पृष्ठ जाए तो पुनः लगा दें।

आवश्यकता आपकी सुविधा हमारी
Contact For Advertisement Booking
Ring Road No.-2, Gourav Path, Bilaspur
Mo.- 9826782100

आवश्यकता है	आवश्यकता है –बिलासपुर की निर्माणाधीन कॉलोनी में सिविल कॉन्ट्रक्टर (छत नापी+ आइएम रेट) प्लास्टर एवं कोन्ट्रक्टर, शटरिंग लोहार, टाइल्स कॉन्ट्रक्टर की आवश्यकता है सम्पर्क करें- 9589000659, 799992 9926900549 (40528)
--------------------	--

आवश्यकता है – अनुभववी कार ड्राइवर की आवश्यकता है जो सभी प्रकार की कार चलाने में सक्षम हो (Manual/ Automatic) शाकाहारी को प्राथमिकता मासिक पेमेन्ट योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- 9301922223 (40573)
--

आवश्यकता है – होटल में कार्य करने हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर चाहिए वैतन 11000 से 13000 (समय सुबह 8बजे से शाम 8बजे) पता- होटल रॉयल रामा, पुराना बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज रोड बिलासपुर 9893392495 (40574)
--

आवश्यकता है – सीबीएसई स्कूल में PGT, TGT, PRT, Pre Primary (बौण्ड अनिवार्य) टीचर्स, हिन्दी टाईपिस्ट एवं आया दीदी की आवश्यकता है। सम्पर्क- मॉडर्न एजुकेशनल एकेडमी, आरएसके कम्पाउंड नया संकरण्डा, बिलासपुर 9109139971, 9301275222 (40562)
--

आवश्यकता है – भवानी ट्रेसर्स चकरभाटा बिलासपुर (एशियन पेंट्स, एसीसी सीमेन्ट, गोयल टीएमटी अधिकृत डीलर) को 12 पद अनुभववी डाटा एंट्री ऑपरेटर युवक/ युवती चाहिए वैतन योग्यता अनुसार अनुभव 5-7 वर्ष सम्पर्क समय 12बजे से शाम 6बजे तक 93037 90515, 96669365848 (40549)
--

आवश्यकता है –राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी को अपने ऑफिस विस्तार हेतु अविवाहाित युवकों की आवश्यकता है जो शहर से बाहर छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र में रहकर काम कर सके वैतन 12000 रहना खाना निवृक्ति फ्री ट्रेनिंग के बाद कमाये 20 से 25 हजार महीना सम्पर्क करे 9755577072, 7999141133 (401)
--

आवश्यकता है –इलेक्ट्रीकल थ्रीव्हीलर शोरूम में फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव 6 पोरट (युवक, युवतियां) एवं टेकनीशियन 6 पोरट चाहिए। वेतन योग्यतानुसार सम्पर्क करें- मालवा टीवीएस मेन रोड न्यूपार विहार बिलासपुर 8827948333, 93400 93263 (40555)

आवश्यकता है –दवाई दुकान में काम करने के लिए लड़कों की आवश्यकता है। वैतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- शिवकुमार रमेश कुमार ज्वेलर्स। सरद बाजार बिलासपुर 93012 88666, 9827932666 (40579)
--

आवश्यकता है –ड्राइवर की आवश्यकता है (घर एवं दुकान में गाड़ी चलाने हेतु एवं अन्य कार्य) वैतन 12000 से योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें- शिवकुमार रमेश कुमार ज्वेलर्स। सरद बाजार बिलासपुर 93012 88666, 9827932666 (40579)
--

आवश्यकता है – दुकान में काम करने के लिए लड़के एवं लड़कियों की आवश्यकता है। पता- गोविन्द इलेक्ट्रॉनिक बुधवारी बाजार गेट नंबर 1, सम्पर्क करें- 9300635599 (40566)
--

आवश्यकता है –सिक्किमिटी का कार्य करने के लिए (जो शोरूम में गाड़ियों की एंट्री कर सके) की आवश्यकता है अनुभववी को प्राथमिकता सम्पर्क करें- 9981630084, 9425534940 (40561)
--

आवश्यकता है –श्री गुरुतेग बहादुर उ.म। शाला 27खाली, विकास नगर में हिन्दी/ अंग्रेजी माध्यम हेतु शिक्षकों एवं ऑफिस कार्य हेतु कम्प्यूटर शिक्षक चाहिए। सम्पर्क करें- प्रातः 8 से 12बजे तक 982740 5850, 9039768650 (40543)
--

आवश्यकता है –प्रतिष्ठित कंस्ट्रक्शन कम्पनी में टेली कॉलिंग करने हेतु युवती एवं चार्ज पानी साफ सफाई करने के लिए युवक एवं युवती की आवश्यकता है सम्पर्क करें- बिलासपुर 9039190256 (40559)

आवश्यकता है –इलेक्ट्रीशियन- 2 (बेटीरी ऑटो में वायिंग कार्य के अनुभववी ही सम्पर्क करें) हेल्पर- 4 श्री व्हीलर ऑटो के कार्य के अनुभव ही सम्पर्क करें- 9303555032, 93030 55032 (40565)
--

आवश्यकता है –यश विग बाजार में काम करने के लिए लड़कियों (सेल्समर्गल) की आवश्यकता है आकर्षक वेतन ESIC सुविधा के साथ सम्पर्क करें- स्टेट बैंक के सामने राजकिशोर नगर बिलासपुर 9300329794, 9131876031 (40554)

आवश्यकता है – फार्मासिस्ट (मेलें) बेसिक कम्प्यूटर नॉलेज, आया बाई (फोमेल) चाहिए वैतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- सुबह 11बजे से 2बजे तक उदय चिल्ड्रन हास्पीटल वेयर हाउस रोड बिलासपुर 9753434748 8085812980 (40553)
--

आवश्यकता है –साफ सफाई गार्डन में पानी डालने एवं अन्य सभी घरेलू कार्य करने के लिए लुढ़के की आवश्यकता है रहने, खाने की सुविधा दी जाएगी तनखा- 7500 महीना सम्पर्क करें- 7869399765 (40544)

आवश्यकता है –पाट दाईम फील्ड कार्य के लिए 2 स्थानीय कैमरा सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं ऑफिस स्टाफ (लड़के/ लड़कियां) की आवश्यकता है। सम्पर्क करें- 8878181720, 8889022217 (40567)
--

आवश्यकता है –राष्ट्रीय स्तर की कम्पनी को अपने ऑफिस विस्तार हेतु अविवाहाित युवकों की आवश्यकता है जो शहर से बाहर छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र में रहकर काम कर सके वैतन 12000 रहना खाना निवृक्ति फ्री ट्रेनिंग के बाद कमाये 20 से 25 हजार महीना सम्पर्क करे 9755577072, 7999141133 (401)
--


बेचना है –10×14 की दुकान छत नहीं नरेश बाजार के अन्दर मां शारदा कॉम्प्लेक्स तेलीपारा, 10×14 दुकान मेन रोड पर (सेलरी 15,000 - 18,000) 2. मुंशी 3. लेबर (कुली, रेजा) रहने की व्यवस्था है। संपर्क : 79879-70711 (2602) 8770963388 (40556)
बेचना है –सकरी मेन रोड, जैन इंटरनेशनल स्कूल के पास विकसित कॉलोनी में कमर्शियल शॉप्स। बेहतर रेन्टल इंकम। मुख्य सड़क से लग्नी पाँश कॉलोनी 3BHJK प्रीमियम लक्जरी हाउस बेचना है सुविधाएं अंडर ग्राउंड इलेक्ट्रीसिटी, 24×7 CCTV, क्लब हाउस, गार्डन, मन्दिर सीमित यूनित्स सम्पर्क- 7799957000, 8109412221 (40424)
किरया
किरया – मंगला चौक पर सागर गोल्डन स्क्वेयर काम्प्लेक्स में प्रथम तल पर 12×17 की दो दुकानें किराए से देना है सम्पर्क करें- 93032 05444 (40571)

सूचना

पाठकों से अनुरोध है कि वे समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कदम उठाने (पैसे भेजने, कोई भी खर्च उठाने, चिकित्सकीय सलाह, विवाह संबंधित) या किसी भी वादे-दावे पर अमल करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। पाठक पूर्ण जानकारी लेवे व स्वविवेक से निर्णय लेकर ही लेन देन करें। किसी भी उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किए किसी भी विज्ञापनदाता के किसी प्रकार के दावों की हरिभूमि (प्रेस प्रबंधक व कर्मचारी) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रकाशक, संपादक, कर्मचारी और हरिभूमि के स्वामी किसी विज्ञापन के संबंध में उठाए किसी कदम के नतीजे और विज्ञापन दाताओं के अपने वायदों पर खरा न उतरने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

पेट सफा Laxative Green Tea **Sirf Ek कप चाय,** **कब्ज को Tata Bye-Bye**

पेट सफा... तो हर रोग दफा

अगर आपका पेट भी सुबह पूरी तरह से साफ नहीं होता तो इससे छुटकारा अब बिल्कुल आसान है, रात को सोते समय 'पेट सफा' Laxative Green Tea का सिर्फ एक कप पीना है, और सुबह आपका पेट होगा, एक झटके में बिल्कुल साफ और Fresh.

Buy Now: amazon | Flipkart | blinkit | imo | bigbasket | snapdeal | JioMart

24 हजार साल बाद 'नींद' से जागा पाषाण युग का यह रहस्यमयी जीव

जिंदा होते ही जो किया उसे देख वैज्ञानिक भी हैरान!

मास्को। जरा सोचिए कि कोई जीव तब गहरी नींद में सो गया हो जब इस धरती पर हिम युग रहा हो, धरती पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो और आज के आधुनिक युग में जब वह जागा, तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हजारों साल पहले था। रूस के साइबेरियाई इलाके में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा ही मिला है जिसे सुनकर प्रकृति के नियमों पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने परतों में 24,000 साल से दबे एक

क्या है यह जीव?

रूसी वैज्ञानिक ने जिस जीव को खोजा है उसका नाम रॉटफर है। यह एक बहुकोशिकीय जीव है जो आमतौर पर मोठे पानी में मिलता है। रॉटफर अपनी मजबूती के लिए जाने जाते हैं, ये कम ऑक्सीजन, भुखमरी और बहुत ही ज्यादा ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। अब तक माना जाता था कि ये जीव जमने के बाद सिर्फ 10 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस नई खोज ने पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं।



कैसे हुआ यह चमत्कार?

रूस के सायल कार्यालयोंजी लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की अलाजेया नदी के पास मिट्टी के नमूने लिए थे। इसके बाद रेडियोकार्बन डेटिंग हुआ जिसमें पता चला कि यह जीव करीब 24,000 साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह जीव फिफ्टोब्रायोसिस स्थिति में चला गया था। इस अवस्था में शरीर का मेटाबॉलिज्म करीब करीब पूरी तरह रुक जाता है, जिससे जीव हजारों सालों तक शांत अवस्था में बना रहता है।

मानव गविय के लिए क्यों है अहम?

रिसर्च के लेखक स्टैस मालविन का कहना है कि एक जटिल बहुकोशिकीय जीव जिसके पास दिमाग और पाचन तंत्र भी होता है, को इतने सालों बाद जीवित होना एक बड़ी उपलब्धि है। यह कई फिक्शन लेखकों के सपने जैसा है। लेकिन, इंसानों के लिए अभी यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे जीव का सिंगल सेल से निकलकर जटिल संरचना के साथ वापस लौटना विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सूक्ष्म जीव को पुनर्जीवित कर लिया है, जीव होश में आते ही अपनी नई दुनिया भी बसानी शुरू कर दी। रूस के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया की जमी हुई बर्फ से एक ऐसे छोटे जीव की खोज की है, जो बीते 24,000 सालों से बर्फ में जमा था, मानों कोमा वाली स्थिति में था। जैसे ही रूसी वैज्ञानिकों ने इसे गर्माहट देकर पिघलाया, तो वह न सिर्फ जिंदा हो गया, बल्कि इसने प्रजनन करना भी शुरू कर दिया।

कैलिफोर्निया का यह पेड़ है जंगल का 'नेचुरल एसी'

वॉशिंगटन। धरती पर जब भी सबसे वजनी जीव की बात होती है, तो ब्लू व्हेल का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन कैलिफोर्निया का एक पेड़ इस दावे को भी छोटा कर दे रहा है। जनरल शर्मन नाम का एक पेड़ 14 ब्लू व्हेल्स से भी ज्यादा वजनी है। सबसे ज्यादा चौकाने वाली बात इसकी बनावट है। इतना वजनी होने के बाद भी इसकी जड़ें मात्र 6 फीट गहरी हैं। यह पेड़ वनस्पति विज्ञान के सारे पैमानों को छोटा साबित कर देता है।

विशाल पेड़ का नाम है जनरल शर्मन

कैलिफोर्निया में स्थित सेक्वाइया नेशनल पार्क में मौजूद इस विशाल पेड़ का नाम जनरल शर्मन है। नेशनल पार्क सर्विस के डेटा के मुताबिक, जनरल शर्मन पेड़ के सिर्फ तने का ही आयतन ही 52,500 क्यूबिक फीट है। अगर इसकी टहनियों और जड़ों के वजन को भी शामिल कर लिया जाए, तो इसका कुल वजन करीब 2,100 टन तक पहुंच जाता है। एक औसत ब्लू व्हेल का वजन 150 से 190 टन होता है, इस लिहाज से यह अकेला पेड़ एक दर्जन से ज्यादा व्हेल्स से भारी है।

2100 टन वजन, लेकिन जड़ें सिर्फ 6 फीट गहरी!



यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये पेड़ सिर्फ शोपेंस नहीं होते हैं, बल्कि चलते-फिरते वाटर प्यूरीफायर और एयर कंडीशनर का भी काम करते हैं। एक मेट्रो सेक्वाइया पेड़ अपनी पत्तियों और हाइड्रोलिक प्रेशर के जरिए हर दिन सैकड़ों गैलन पानी वाष्पित करता है। इससे न सिर्फ जल चक्र बना रहता है, बल्कि जंगल का तापमान भी नियंत्रित रहता है, जिससे हजारों दूसरे प्रजातियों को जीवन मिलता है।

क्यों नहीं रुक रही इसकी वृद्धि?

ज्यादातर इस प्रजाति के पेड़ एक समय के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन सेक्वाइया के साथ ऐसा नहीं हुआ है। यह अपनी पूरी जिंदगी जो करीब 3,000 साल तक हो सकती है, तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी छाल में टैनिन नाम का केमिकल बहुत ज्यादा है। यह केमिकल इसे कीड़ों के हमले, सड़न और यहां तक कि आग से भी बचाता है। यही कारण है कि यह पेड़ सदियों तक जीवित रहकर भी भारी मात्रा में कार्बन सोखता रहता है।



देवी की मूर्ति के नीचे दफन है अरबों की दौलत?

शिवपुरी। इतिहास की किताबों में राजा नल और दमयंती की कहानियां तो लगभग हर किसी ने सुनी होंगी, लेकिन मध्यप्रदेश के ग्वालियर के पास नरवल किले में इन दिनों कुछ अलग ही कहानी चल रही है। नरवल किले की एक ऐसी लोककथा, जिसमें अरबों के सोने और सदियों पुराने शाही खजाने का जिक्र है। कहा जाता है कि यहां की लेटी हुई देवी की प्रतिमा के नीचे राजा की दौलत दफन है। इस दावे को लेकर चौकाने वाला खुलासा तक हुआ, जब एएसआई संरक्षित क्षेत्र में एक गहरी सुरंग सामने आई। सिक्कों की गूंज और धातु की आवाज ने खजाना चोरों को दावत दी, और



नरवल किले में देजर हंटर्स की इस गुस्ताखी से नचा हड़कंप

फिर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास शिवपुरी जिले में स्थित ऐतिहासिक नरवल किले में खजाने की खोज को लेकर हैरान कर देने वाला मामला आया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित इस प्राचीन किले में संदिग्ध शिकारियों ने मां पसार देवी मंदिर के पीछे करीब 20 फीट गहरी सुरंग खोद डाली है।

राजा नल और खजाने की लोककथा

चोरी से इस सुरंग की खुदाई के पीछे की प्रमुख वजह है इस किले के मंदिर को लेकर पुरानी लोककथा है। स्थानीय मान्यता है कि राजा नल ने अपना राज्य हारने के बाद अपने शाही खजाने की सुरक्षा के लिए मां पसार देवी की लेटी हुई मूर्ति को किले के अंदर पर स्थापित किया था। लोगों का मानना है कि इस मूर्ति के ठीक नीचे राजा की पूरा खजाना दबा हुआ है।

कैसे हुआ खुलासा?

स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर के पीछे झाड़ियों से छिपाकर यह खुदाई हुई थी। इस मौके पर पहुंची पुलिस टीम को वहां से खुदाई के औजार, एरोसोल स्प्रे कैन और कंबल मिले हैं। इन सामानों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से वहां रात के समय में सुरंग खोज रहे थे और दिन में सुरंग को झाड़ियों से ढक दिया करते थे, जिससे किसी को शक हो ही ना। खजाने के इस दावे को और भी बल मिलता है देवी मूर्ति के पास एक ऐसी जगह है, जहां सिक्का डालने पर धातु से टकराने जैसी गूंज सुनाई देती है। इसी आवाज ने खजाना होने के संभावना को और बल दिया।

कालड़ा बर्न एवं प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर



होंठों को पतला - मोटा करें और आकर्षक बनायें, इंजेक्शन व लेसर द्वारा

डॉ. ज. शानवत से मान्यता प्राप्त
आर.के.सी.के.सामने, चौथे फ्लोरी एवं पंचरंगी नाका, धमलपुरी रोड कलर्स मॉल के पास, रायपुर
कॉल : 9827143060/8871003060
Ajay Adv.

HONDA
The Power of Dreams

How we move you.
CREATE ► TRANSCEND, AUGMENT

नए रिश्तों की

Shine 100DX



डिजिटल मीटर

एवरेंज माइलेज इंडिकेटर | लाइव माइलेज इंडिकेटर | रेंज इंडिकेटर

एक्स-शोरूम (मतीसगढ़)
₹70196

अधिक जानकारी के लिए **7230032200** पर मिसड कॉल दें

5-स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन

ट्यूबलेस टायर्स

स्टाइलिश क्रोम प्लेटिंग

वाइड फ्यूल टैंक

कम डाउन पेमेंट
₹7499*

इंस्टैंट कैशबैक
₹5000*

न्यूनतम ब्याज दर
@6.99%*

बिना हाइपोथिकेशन*

*Terms and Conditions applied. #5% Instant Cashback up to Rs. 5000 is available on all HMSI models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of Rs. 40000 (Tenure 6 months & above). #Instant Cashback of up to Rs. 4000 is available on selected HMSI models for EMI transactions using IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of Rs. 40000 (Tenure 9 months & above). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 30th April 2026. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 30th April 2026. The feature shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; Website: www.honda2wheelerindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **BILASPUR:** Dream Honda - 9926802408; Maosaji Honda - 7024149881; **AKALTARA:** Bhagwati Honda - 9827527016; **AMBIKAPUR:** Mahamaya Honda - 7489027000; Jaswani Honda - 8358065000; **BAIKUNTHPUR:** Pramila Honda - 7000405012; **BARADWAR:** Ganpati Honda - 7974875687; **BILHA:** Sai Honda - 9179256022; **KAWARDA:** Pratha Honda - 7400550099; **DHARAMJAGARH:** Harsh Honda - 9424180180; **DIPKA:** Kamal Honda - 9111144667; **JANJIR CHAMPA:** Gattani Honda - 7694011206; Shubh Honda (Baloda) - 8574921111; **JASHPUR:** Deo Narayan Honda - 94252251702; **KHARSIA:** Balaji Honda - 8269515770; **KORBA:** Vishal Honda - 9479025937; Krishna Korba Honda - 7747015377; JP Honda (Hardi Bazar) - 9826129114; Ashwini Honda (Urga) - 6232103023; Bharat Honda (Gevra Basti) - 09301001739; **KOTA:** Prakash Honda - 9826417995; **KUNKURI:** Mansharam Honda - 8103798783; **LAILUNGA:** Atul Honda - 9424188280; **LORMI:** Mansi Honda - 9685010000; **MANENDRAGARH:** Harsh Honda - 9993883343; **MASTURI:** Rahul Honda - 9098619245; **PALI:** Mahamaya Honda - 8770804342; **PANGARH:** Gautam Honda - 8962109746; **PANDARIYA:** Shri Balaji Honda - 7399330099; **PATHALGAON:** Dinesh Honda - 9993199987; **PENDRA ROAD:** Dev Honda - 9752998221; **RAHOD:** Shri Balaji Honda - 9977311242; **RAJGARH:** Sharda Honda - 8103664400; Shanti Auto Honda - 9343609280; **RAJPUR:** Maa Mahamaya Honda - 9424259688; **RAMANUJGANJ:** Vikas Honda - 9926158556; **RATANPUR:** Sunil Honda - 9893354893; **SAKTI:** Maa Durga Honda - 9685927215; **SARAIPALI:** Pukhraj Honda - 8889798000; **SARANGARH:** Shanti Honda - 9201826679; **SARSIVA:** Kanisk Honda - 9575533947; **SHEORINARAYAN:** Arav Honda - 9713022700; **SITAPUR:** Akash Honda - 9617378301; **PRATAPUR:** Shri Banbhori Honda - 8120806101; **SURAJPUR:** Maa Mahamaya Honda - 8223999666; **TAKHATPUR:** Dream Honda - 9303005917; **TAPKARA:** Jindal Honda - 9406384666; **WADRUFNAGAR:** KP Auto - 9826881578; **BILASPUR SAKRI:** Dream Honda Branch - 9516661444; **BILASPUR DAYALBANDH:** Maosaji Honda Branch - 9109690484; **GAURELLA:** Shyam Honda - 7024806222; **AHAWARA:** Kabiram Honda - 8319225193; Shree Sairam Honda (Risali) - 8823050333; **DANTEWADA:** Ansh Honda - 7000396031; **NEHRU NAGAR:** Aan Honda - 8518020999; **MUNGELI:** S. Mansi Honda - 9685010000; **BATAULI:** Ankan Honda - 9203617070; **CHOWKI:** Manraj Honda - 9424153947.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in